सांध्य दैनिक
नई दृष्टिबिंदु
सच की शक्ति, जनता की दृष्टि
PRGI Reg No - CTHIN/25/A3746

सु-विचार

" इंसान की पहचान उसके चेहरे से नहीं,
वक्त आने पर उसके व्यवहार से होती है....!! "

अज्ञात...

वर्ष–01 अंक–178 | संपादक आलोक तिवारी | दुर्ग, शुक्रवार 17 जुलाई 2026 | पृष्ठ 08 | मूल्य –2 रुपए

मैनपाट में 'नाशपाती' की मिठास : एग्री–टूरिज्म का नया गढ़ बना छत्तीसगढ़ का शिमला

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में अब नाशपाती की खेती किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ एग्री–टूरिज्म का नया केंद्र बनकर उभरी है। राज्य सरकार की उद्यानिकी योजनाओं और अनुकूल जलवायु ने यहां पारंपरिक खेती को फलोद्यान में बदल दिया है। मैनपाट के ग्राम बारिमा निवासी प्रगतिशील किसान मनोज यादव इसकी जीती–जागती मिसाल हैं। ग्राम कुदारीडीह में मेहता पॉइंट के पास उन्होंने नाशपाती का सफल बागान तैयार कर न सिर्फ अच्छी कमाई की, बल्कि पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना दिया।

बंजर जमीन पर लहलहाए 170 पेड़ : मनोज यादव ने बताया कि वर्ष 2017–18 में उन्होंने कमलेश्वरपुर स्थित शासकीय उद्यान रोपणी से नाशपाती के पौधे लिए थे। अपनी 0.500 हेक्टेयर गोड़ा जमीन पर 200 पौधे लगाए। प्राकृतिक कारणों से कुछ पौधे नष्ट हुए, लेकिन आज उनके पास 170 पूरी तरह फलदार वृक्ष हैं। इस सफलता का श्रेय वे उद्यानिकी विभाग को देते हैं। विभाग के अधिकारी समय–समय पर बागान का निरीक्षण कर खाद और रखरखाव के लिए तकनीकी मार्गदर्शन देते हैं।

ओलावृष्टि के बाद भी 1.5 लाख का मुनाफा : इस साल ओलावृष्टि और बाजार में देरी के बावजूद मनोज के बागान से 2.5 पिक अप यानी करीब 260 कैरेट नाशपाती का उत्पादन हुआ। थोक में 500 रुपये प्रति कैरेट की दर से लगभग 1.30 लाख रुपये की आय हुई। इसके अलावा खुले बाजार और पर्यटकों को सीधे बिक्री से 25–30 हजार रुपये और मिले। इस तरह इस सीजन में उन्हें 1.5 लाख रुपये की शुद्ध आय हुई। पिछले साल अनुकूल मौसम में इसी बागान से 2.5 से 3 लाख रुपये की बंपर कमाई हुई थी।

किसान मनोज यादव की बदली किस्मत

पर्यटकों के लिए बना आकर्षण : कुदारीडीह स्थित यह बागान अब एग्री–टूरिज्म का हॉटस्पॉट बन गया है। लालमाटी से रायगढ़ क्षेत्र का मनोरम दृश्य देखने रोजाना 100 से 250 पर्यटक पहुंचते हैं। वे यहां 50 से 100 रुपये किलो ताजी नाशपाती खरीदने के साथ खुद पेड़ से फल तोड़ने का आनंद भी लेते हैं। इससे किसानों को बिचौलियों के बिना सीधे बिक्री का मौका मिल रहा है।

युवाओं के लिए प्रेरणा : मनोज यादव ने क्षेत्र के युवाओं और किसानों से अपील की है कि वे खाली पड़ी जमीन पर नाशपाती, लीची जैसे फलदार पौधे लगाएं। कम रकबे में अधिक मुनाफा और पर्यटन क्षेत्र के पास सीधी बिक्री से अतिरिक्त लाभ मिलता है।

जिला प्रशासन और उद्यानिकी विभाग वनांचल क्षेत्रों में फलोद्यान विकास, आधुनिक प्रशिक्षण और तकनीक के जरिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहा है। मनोज यादव जैसे किसान साबित कर रहे हैं कि वैज्ञानिक मार्गदर्शन और मेहनत से बागवानी को लाभ का बड़ा व्यवसाय बनाया जा सकता है।

सीएम साय ने दोकड़ा की ऐतिहासिक रथयात्रा में निभाई गजपति महाराजा की परंपरा

भगवान श्री जगन्नाथ का रथ खींचकर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर-जशपुर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर जिले के कांसाबेल विकासखंड स्थित ग्राम दोकड़ा में आयोजित ऐतिहासिक श्री जगन्नाथ रथयात्रा महोत्सव–2026 में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय के साथ परंपरागत गजपति महाराजा की भूमिका का निर्वहन करते हुए भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र एवं देवी सुभद्रा की विधिवत पूजा–अर्चना की तथा प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, खुशहाली और स्वास्थ्य की कामना की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने छेरा पहरा की पावन परंपरा का निर्वहन करते हुए सोने की झाड़ू से भगवान के रथ के आगे मार्ग का प्रतीकात्मक रूप से मार्जन किया तथा चंदन मिश्रित पवित्र जल का छिड़काव किया। इसके बाद उन्होंने हजारों श्रद्धालुओं के साथ भगवान श्री जगन्नाथ के रथ की रस्सी खींचकर रथयात्रा का शुभारंभ किया। पूरे दोकड़ा क्षेत्र में "जय जगन्नाथ" के जयघोष, शंखध्वनि, भजन–कीर्तन और हरिनाम संकीर्तन से वातावरण भक्तिमय हो उठा। मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी श्रद्धालुओं को रथयात्रा की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि दोकड़ा की ऐतिहासिक रथयात्रा आस्था, संस्कृति और सनातन परंपराओं का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1942 से चली आ रही यह गौरवशाली परंपरा आज भी जनआस्था को नई ऊर्जा प्रदान कर रही है। जनसहयोग से मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और वर्ष 2025 में प्राण–प्रतिष्ठा के बाद यह दूसरी भव्य रथयात्रा आयोजित हो रही है। उन्होंने गजपति महाराजा की परंपरा निभाने का अवसर देने के लिए दोकड़ावासियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ का भगवान श्री जगन्नाथ से प्राचीन और आत्मीय संबंध रहा है। देवभोग का चावल आज भी पुरी के महाप्रसाद में उपयोग किया जाता है, जो इस सांस्कृतिक संबंध का जीवंत प्रमाण है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की गारंटी के अनुरूप प्रदेश में 11 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। महतारी वंदन योजना की 29 किस्तें जारी की जा चुकी हैं तथा रामलला दर्शन और मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना के माध्यम से हजारों श्रद्धालु लाभान्वित हुए हैं। राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास को भी प्राथमिकता दी जा रही है।

इस अवसर पर पद्मश्री जागेश्वर यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, कमिश्नर नरेंद्र दुग्गा, आईजी दीपक कुमार झा सहित श्री जगन्नाथ मंदिर आयोजन समिति के सदस्य तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।

श्रद्धा और उत्साह के साथ निकली भगवान श्री जगन्नाथ रथयात्रा

सांसद विजय बघेल ने खींचा रथ, हजारों श्रद्धालु हुए शामिल

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

भगवान श्री जगन्नाथ जी की पावन रथयात्रा बुधवार को भिलाई में श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र एवं देवी सुभद्रा के दर्शन किए। दुर्ग सांसद विजय बघेल भी विभिन्न स्थानों से निकलने वाली जगन्नाथ यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने रथ की रस्सी खींचकर पुण्य लाभ अर्जित किया।

पूरे मार्ग में "जय जगन्नाथ" के जयघोष, भजन–कीर्तन और शंख–घंटों की गूंज से धार्मिक वातावरण बना रहा। यात्रा के समापन पर अखरा पाटन स्थित भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी मंदिर ट्रस्ट में सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों द्वारा श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, प्रसाद और अन्य सेवा व्यवस्थाएं की गई।

सामाजिक समरसता का प्रतीक रथयात्रा : इस अवसर पर राजा पाठक, बाबा वर्मा, रोशन वर्मा, डोनेश्वर साहू, अमर चंद वर्मा, रुपेन्द्र वर्मा, जगनूराम वर्मा, केदार कश्यप, महेंद्र वर्मा, सुनील वर्मा, शरद बघेल, नागेन्द्र कश्यप, प्रहलाद कश्यप, राजेश वर्मा, रंजना वर्मा, पुरेन्द्र वर्मा, नारायण वर्मा सहित जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने कहा कि भगवान श्री जगन्नाथ की रथयात्रा सामाजिक समरसता, भाईचारे और भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को रथयात्रा की शुभकामनाएं देते हुए भगवान जगन्नाथ से प्रदेश एवं देश की सुख–समृद्धि, शांति और जनकल्याण की कामना की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे।

भगवान श्री जगन्नाथ की पावन रथयात्रा बुधवार को नगर में श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ने इस धार्मिक आयोजन में सहभागिता कर रथयात्रा को विशेष बना दिया।

उत्कल सांस्कृतिक परिषद सेक्टर-6 : सांसद विजय बघेल ने सेक्टर–6 स्थित उत्कल सांस्कृतिक परिषद, श्री गुण्डिचा मंडप श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र एवं देवी सुभद्रा की विधिवत पूजा–अर्चना एवं आरती की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश और देश की सुख–समृद्धि, शांति एवं जनकल्याण की कामना की।

रथ खींचकर लिया पुण्य लाभ : मंदिर समिति के दिलीप महन्ती, अरुण पण्डा, प्रशांत सामल, शरद बिस्वाल और ब्रिजेश बिचपुरी ने सांसद विजय बघेल का पुष्पगुच्छ भेंटकर आत्मीय स्वागत किया। इसके पश्चात सांसद ने श्रद्धालुओं के साथ मिलकर भगवान श्री जगन्नाथ के रथ को खींचा और पुण्य लाभ अर्जित किया।

सांसद विजय बघेल ने इसके बाद पाटन स्थित भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी मंदिर ट्रस्ट अखरा की रथयात्रा में भी भाग लिया। यात्रा के दौरान पूरा मार्ग "जय जगन्नाथ" के जयघोष, भजन–कीर्तन और धार्मिक उल्लास से गुंजायमान रहा। मार्ग में विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों द्वारा श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, प्रसाद एवं अन्य सेवा व्यवस्थाएं की गई।

सामाजिक समरसता का प्रतीक रथयात्रा : इस अवसर पर सांसद विजय बघेल ने कहा कि भगवान श्री जगन्नाथ की रथयात्रा भारतीय संस्कृति, सामाजिक समरसता, भाईचारे और लोककल्याण की महान परंपरा का प्रतीक है। यह पर्व समाज को एकता, सेवा और सद्भाव का संदेश देता है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को रथयात्रा की शुभकामनाएं देते हुए भगवान श्री जगन्नाथ से सभी के जीवन में सुख, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की।

कार्यक्रम में राजा पाठक, बाबा वर्मा, रोशन वर्मा, डोनेश्वर साहू, अमरचंद वर्मा, रुपेन्द्र वर्मा, जगनूराम वर्मा, केदार कश्यप, महेंद्र वर्मा, सुनील वर्मा, शरद बघेल, नागेन्द्र कश्यप, प्रहलाद कश्यप, राजेश वर्मा, रंजना वर्मा, पुरेन्द्र वर्मा, नारायण वर्मा सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे।

सेक्टर-4 में भारी श्रद्धा के साथ निकली महाप्रभु जगन्नाथ की रथयात्रा

बीएसपी डायरेक्टर इंचार्ज चितरंजन महापात्र ने किया छेरा–पंहरा, हजारों भक्तों ने खींचा रथ

भक्ति और आस्था के जयकारों के साथ बुधवार को सेक्टर–4 बोरिया मार्केट स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर से भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी की रथयात्रा निकाली गई। यात्रा में उमड़ी भारी भीड़ और "जय जगन्नाथ" के उद्घोष से पूरा सेक्टर जगमगा उठा। जगन्नाथ समिति के तत्वाधान में निकली यह रथयात्रा सेक्टर–4 मंदिर से प्रारंभ होकर सेन्ट्रल एवेन्यू होते हुए सेक्टर–10 स्थित भव्य गुण्डिचा मंडप पहुंची।

बीएसपी डायरेक्टर इंचार्ज ने की छेरा-पंहरा परंपरा

इस वर्ष रथयात्रा के मुख्य अतिथि बीएसपी के डायरेक्टर इंचार्ज श्री चितरंजन महापात्र रहे। पुरी की परंपरा के अनुसार उन्होंने रथ के समक्ष छेरा–पंहरा कार्यक्रम संपन्न किया। इसके बाद भगवान श्री बलभद्र, माता सुभद्रा और महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के विग्रहों को पंडुली कर काष्ठ निर्मित भव्य रथ पर विराजमान किया गया। छेरा–पंहरा के पश्चात भक्तों ने जयघोष के साथ रथ खींचना शुरू किया।

झांझ–मंजीरे और भजनों की गूंज

रथयात्रा के दौरान झांझ, मंजीरे, ढोल–मृदंग बजाते कीर्तन दल और भक्ति संगीत की धुन पर नाचते–गाते श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। सेन्ट्रल एवेन्यू में महाप्रभु के दर्शन के लिए सड़क के दोनों ओर हजारों श्रद्धालु खड़े थे। रथ के पहुंचते ही दर्शन और रथ खींचने के लिए भारी संख्या में लोग उमड़ पड़े। यात्रा मार्ग में विभिन्न संस्थाओं और समाजसेवी संगठनों द्वारा रथ का भव्य स्वागत किया गया। पंडाल लगाकर श्रद्धालुओं को अन्न प्रसाद, गजामूंग प्रसाद, भोग और शर्बत का वितरण किया गया।

समाजसेवी सम्मानित, कई गणमान्य उपस्थित

इस अवसर पर लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष एवं समाजसेवी संजय मिश्रा को उनके सामाजिक कार्यों के लिए "सेवा रत्न पुरस्कार" से सम्मानित किया गया। रथ के कारीगरों और चित्रकारों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में बीएसपी के मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी एम एंड यू बिजय बेहरा, सेफी वेयरमैन एवं ऑफिकर्स एसोसिएशन अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर, महाप्रबंधक अजय कुमार, बीएसपी साइकिल पोलो एवं सेविंग क्लब अध्यक्ष परविंदर सिंह उपस्थित रहे।

जगन्नाथ समिति के अध्यक्ष वीरेन्द्र सतपथी, महासचिव सत्यवान नायक सहित त्रिनाथ साहू, डी त्रिनाथ, अनाम नाहक, वृंदावन स्वांई, बसंत प्रधान, भीम स्वांई, बी.सी. बिस्वाल, प्रकाश स्वांई सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद थे। रथ का संचालन वृंदावन स्वांई, बी.सी. बिस्वाल, श्याम दलाई और लखन बिस्वाल की टीम ने किया। पूजा कर्म पंडित पितवास पाढ़ी एवं उनकी टीम ने विधि–विधान से संपन्न कराए। समिति ने यात्रा को सफल बनाने में सहयोग के लिए सभी श्रद्धालुओं और संस्थाओं का आभार व्यक्त किया।

एमओयू भिलाई इस्पात संयंत्र और टाउनशिप में मिलेगी पाइप्ड नेचुरल गैस, ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा

बीएसपी व अडाणी टोटल गैस के बीच पीएनजी आपूर्ति को लेकर एमओयू

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

सेल–भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) और अडाणी टोटल गैस लिमिटेड (एटीजीएल) के बीच बुधवार को भिलाई इस्पात संयंत्र तथा टाउनशिप में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण–अनुकूल ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ ही संयंत्र की ऊर्जा दक्षता बढ़ाने की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है।

नवींदरजीत सिंह बेदी और भिलाई इस्पात संयंत्र की ओर से मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी (एम एंड यू) बी. के. बेहरा ने एमओयू का आदान–प्रदान किया।

समझौते पर हस्ताक्षर

समारोह में भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के अध्यक्ष एवं पूर्व आईएएस अधिकारी डॉ. अनिल कुमार जैन और बीएसपी के निदेशक प्रभारी चितरंजन महापात्र मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अडाणी टोटल गैस लिमिटेड की ओर से बैठक में संयंत्र में पीएनजी के उपयोग का विस्तार, वर्तमान में प्रयुक्त प्रोपेन और एलपीजी के स्थान पर तकनीकी रूप से व्यवहार्य क्षेत्रों में पीएनजी अपनाने की संभावनाओं और दोनों संस्थानों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान उप प्रबंधक जनसंपर्क शालिनी चौरसिया ने बीएसपी का विस्तृत प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत किया।

ऊर्जा सहयोग पर हुई चर्चा

दीर्घकालिक लाभकारी होगी साझेदारी : निदेशक प्रभारी

निदेशक प्रभारी चितरंजन महापात्र ने कहा कि यह साझेदारी दोनों संस्थानों के लिए दीर्घकालिक रूप से लाभकारी सिद्ध होगी। इससे स्वच्छ और सुरक्षित ईंधन के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा तथा ऊर्जा दक्षता एवं सतत विकास के लक्ष्यों को नई गति मिलेगी।

वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

कार्यक्रम में बीएसपी के कार्यपालक निदेशक ए. के. चक्रवर्ती सामग्री प्रबंधन, प्रवीण निगम वित्त एवं लेखा, पवन कुमार मानव संसाधन, पी. के. सरकार परियोजनाएं, राकेश कुमार संकार्य सहित संयंत्र के मुख्य महाप्रबंधक एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

यह समझौता बीएसपी और उसकी टाउनशिप में पीएनजी की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके जरिए स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन, ऊर्जा प्रबंधन में सुधार और पर्यावरण संरक्षण एवं हरित औद्योगिक विकास के राष्ट्रीय उद्देश्यों को बल मिलेगा।

जिले में अब तक 293.9 मिमी औसत वर्षा दर्ज

सबसे अधिक बोरी में 412.1 मिमी, सबसे कम धमधा में 202.0 मिमी

दुर्ग। जिले में मानसून की शुरुआत से अब तक अच्छी वर्षा दर्ज की गई है। जिला प्रशासन के भू–अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जून 2026 से 16 जुलाई 2026 तक जिले में 293.9 मिमी औसत वर्षा हुई है। आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि में जिले की तहसीलों में अलग–अलग मात्रा में वर्षा दर्ज की गई। सर्वाधिक वर्षा तहसील बोरी में 412.1 मिमी दर्ज की गई है, जबकि न्यूनतम वर्षा 202.0 मिमी के साथ तहसील धमधा में हुई है।

अन्य तहसीलों में दर्ज वर्षा इस प्रकार है। तहसील दुर्ग : 320.4 मिमी, तहसील पाटन : 310.6 मिमी, तहसील भिलाई–3 : 265.7 मिमी, तहसील अहिवारा : 252.7 मिमी। बुधवार 16 जुलाई को जिले में हल्की से मध्यम वर्षा हुई। तहसीलवार आंकड़े इस प्रकार रहे दुर्ग में 0.6 मिमी, धमधा में 0.9 मिमी, पाटन में 0.0 मिमी, बोरी में 35.5 मिमी, भिलाई–3 में 20.7 मिमी और अहिवारा में 17.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

एस. जानकी का भक्ति सुर : 1986 में जयंती स्टेडियम में सराबोर हुआ था भिलाई शहर

दक्षिण की सुर साम्राज्ञी ने भिलाई में गाए थे भजन और फिल्मी गीत

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

पार्श्वगायिका एस. जानकी के निधन 11 जुलाई को दक्षिण भारतीय संगीत जगत में एक युग के अंत जैसा है। दक्षिण की चारों भाषाओं में उन्होंने हर विधा, हर कठिनाई के गीत गाए। हिंदी में उन्हें भले ही ज्यादातर रिमेक फिल्मों के "पूरी कचौरी रसगुल्ला बन जाउंगी", "एक दुपट्टा दो-दो मवाली" जैसे गीत मिले, पर "नाचे मयूरी" का "पग पादम", "झूठी" का "आया जबसे तू दिल में आया", "सत्यमेव जयते" का "दिल में हो तुम आंखों में तुम", "सुर संगम" का "प्रभुजी मोरे अवगुण" जैसे गीत आज भी याद हैं। 1963 में "दिल एक मंदिर" का "पालनहारे राम है" भी उन्हीं की आवाज थी।

लेकिन भिलाई के लिए एस. जानकी की याद सिर्फ फिल्मी गीतों से नहीं, भक्ति से जुड़ी है। व्यस्ततम दौर में भी वह भक्ति संगीत से जुड़ी रहीं। और इसका प्रमाण है 16 नवंबर 1986 की वह शाम, जब जयंती स्टेडियम सिविक सेंटर में उन्होंने भिलाईवासियों को भक्तिरस में डुबो दिया था।

तीन दिवसीय कल्याणोत्सव का हिस्सा बनीं जानकी

भारत सांस्कृतिक एकता समिति मद्रास के तत्वावधान में 1986 में भिलाई में तीन दिवसीय बालाजी संगीत कल्याणोत्सव आयोजित हुआ था। उत्तर भारतीय शास्त्रीय और दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत के दिग्गज यहां एक मंच पर आए थे। पं. जसराज, पं. पुरुषोत्तम जलोटा, पीनाज मसानी, डॉ. बालमुरली कृष्ण और डॉ. रमानी जैसे कलाकारों ने तीन दिन प्रस्तुति दी।

इस आयोजन के तीसरे दिन एस. जानकी मंच पर आईं। उनके साथ सह गायक के रूप में उनके भांजे गरीमेल्ला बालकृष्ण प्रसाद थे। हारमोनियम पर वी.के. कुड्वा ने संगत की। कुड्वा दक्षिण के उन संगतकारों में थे जो पी. सुशीला से लेकर एस.पी. बालसुब्रमण्यम तक के साथ मंच साझा कर चुके थे।

जानकी ने उस शाम भक्ति रचनाएं और अपने कुछ प्रमुख दक्षिण भारतीय फिल्मी गीत प्रस्तुत किए। उस समय वह हिंदी फिल्मों में भी सक्रिय थीं, इसलिए स्टेडियम में दक्षिण भारतीय परिवारों के साथ अन्य भिलाईवासी और शास्त्रीय-कर्नाटक संगीत प्रेमी भी बड़ी संख्या में पहुंचे थे। दशर्कों में बीएसपी के तत्कालीन मैनेजिंग डायरेक्टर के. आर. संगमेश्वरन भी शामिल थे।

भिलाई होटल में हुई मुलाकात

इस आयोजन से जुड़ी यादें आज भी भिलाई के संगीत प्रेमियों के पास हैं। बीएसपी के कोक ओवन एंड कोल केमिकल विभाग सेवानिवृत्त और शौकिया गायक जी.एस. वेंकट सुब्रमण्यम बताते हैं कि जानकी अपनी टीम के साथ भिलाई होटल निवास में ठहरी थीं। वहीं उनसे मुलाकात हुई थी।

उनके पास मौजूद तस्वीरों में एक में मंच पर जानकी के साथ माइक पर गरीमेल्ला बालकृष्ण प्रसाद और हारमोनियम पर वी.के. कुड्वा नजर आते हैं। दूसरी तस्वीर में जानकी के दाईं ओर शंकरा सुब्रमण्यम हैं, जो हाल में बीएसपी के इनकॉस-सीएंडआईटी के विभाग प्रमुख पद सेवानिवृत्त हुए हैं, और बाईं ओर खुद जी.एस. वेंकट सुब्रमण्यम हैं। मंच पर लगी कुसिर्यां सेक्टर-2 के साबिर डेकोरेशन की थीं।

भक्ति और सुर का संगम

एस. जानकी भले ही फिल्मों में अलग-अलग किरदारों के लिए गाती रहीं, पर भिलाई ने उन्हें भक्ति के सुर में सुना। 1986 की उस शाम जयंती स्टेडियम में गूंजा उनका स्वर आज भी कई बुजुर्ग भिलाईवासियों की स्मृति में बसा है। एक ऐसी आवाज जो दक्षिण से उत्तर तक, फिल्म से भजन तक, हर जगह अपनी पहचान छोड़ गई।

खास खबर

शनिचरी बाजार स्थित श्री लंगूर वीर मंदिर में श्रद्धा-भक्ति के साथ हुआ कलश व ध्वजारोहण

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

महापौर बाघमार ने नगर की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की

शहर के ऐतिहासिक शनिचरी बाजार स्थित श्री लंगूर वीर मंदिर में गुरुवार को श्रद्धा, आस्था एवं धार्मिक उल्लास के वातावरण में मंदिर शिखर पर विधि-विधान के साथ कलश एवं ध्वजारोहण का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में महापौर अलका बाघमार शामिल हुईं और भगवान के दर्शन कर नगर एवं प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की।

धार्मिक आयोजन राजू महाराज के सान्निध्य में संपन्न हुआ, जिसमें खेमंत तिवारी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विशेष पूजा-अचर्ना कराई। पूजन के उपरांत मंदिर शिखर पर विधिवत कलश स्थापना एवं ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के साथ ही पूरा मंदिर परिसर जयकारों, भक्ति गीतों और श्रद्धालुओं की आस्था से गुंजायमान हो उठा। इस अवसर पर महापौर अलका बाघमार ने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक एकता को सुदृढ़ करने का कार्य करते हैं।

उन्होंने कहा कि हमारी धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और इसे संजोकर रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, मंदिर समिति के सदस्य, समाजसेवी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। पूजा-अचर्ना के उपरांत सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर रंजीता पाटिल, लोकेश्वरी ठाकुर,मानव सोनकर,आनंद देव ताम्रकार, राजू महाराज, खेमंत तिवारी, लोकेश सोनकर, रोशन कुमार ढीमर, छन्नू यादव, नरेंद्र सोनकर सहित अनेक श्रद्धालु एवं नागरिक उपस्थित रहे।

ओम सत्यम समिति ने मुख्यमंत्री साय से की सौजन्य भेंट, आदिवासी मुखौटा पहनाकर किया सम्मानित

दुर्ग। नगर की ओम सत्यम शिक्षण एवं जन विकास समिति के 31वें स्थापना दिवस के अवसर पर समिति के अध्यक्ष सीताराम ठाकुर एवं सचिव दिलीप ठाकुर ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से विधानसभा परिसर में सौजन्य भेंट की। इस दौरान समिति के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को संस्था की पिछले 31 वर्षों से संचालित शैक्षणिक, सामाजिक एवं जनकल्याणकारी गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। समिति द्वारा शिक्षा, सामाजिक जागरूकता एवं जनसेवा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया। भेंट के दौरान समिति की ओर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति का प्रतीक पारंपरिक आदिवासी मुखौटा पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समिति के 31 वर्षों से निरंतर किए जा रहे सेवा कार्यों की सराहना करते हुए संस्था के पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दीं। समिति के अध्यक्ष सीताराम ठाकुर एवं सचिव दिलीप ठाकुर ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन एवं शुभकामनाओं से संस्था को समाजहित में और अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी।

दुर्ग में स्कूली बच्चों के लिए जिले का पहला 'न्योता भोजन' का किया गया आयोजन

300 से अधिक विद्यार्थियों ने किया पौष्टिक भोजन

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

जन समर्पण सेवा संस्था, दुर्ग ने बुधवार को जिले में स्कूली बच्चों के लिए पहला 'न्योता भोजन' आयोजित कर एक प्रेरणादायी पहल की। यह आयोजन शहर की ऐतिहासिक सरदार वल्लभभाई पटेल प्राथमिक शाला, लाल बहादुर प्राथमिक शाला तथा सरदार पटेल आत्मानंद अंग्रेजी विद्यालय परिसर में किया गया, जिसमें तीनों विद्यालयों के 300 से अधिक विद्यार्थियों ने पौष्टिक भोजन ग्रहण किया।

पोषण निर्माण योजना के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को अतिरिक्त पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना, समुदाय में सहभागिता बढ़ाना तथा बच्चों में समानता और अपनत्व की भावना विकसित करना रहा। जन समर्पण सेवा संस्था द्वारा आयोजित इस न्योता भोजन में श्रीराम कैटर्स के राम भाऊ ने पूड़ी, दाल, चावल, पनीर की सब्जी, हरी सब्जी, मिष्ठान एवं नमकीन सहित स्वादिष्ट भोजन तैयार किया।

कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों को एक साथ बैठाकर शिक्षा, विद्यालय और उसके गौरवशाली इतिहास की जानकारी देने से हुई। संस्था के अध्यक्ष एवं विद्यालय के पूर्व छात्र योगेंद्र शर्मा 'बंटी' ने बताया कि सरदार वल्लभभाई पटेल प्राथमिक शाला वर्ष 1903 में स्थापित हुई थी और यह छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने विद्यालयों में शामिल है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 1933 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस विद्यालय में आए थे तथा यह देश के शुरुआती विद्यालयों में से एक था, जहां सभी वर्गों के बच्चे एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जन समर्पण सेवा संस्था की मानव सेवा, गौ सेवा और न्योता भोजन जैसी सामाजिक पहल की सराहना की। शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि पांडेय ने कहा कि इस तरह के आयोजन जिले के प्रत्येक विद्यालय में होने चाहिए, जिससे समाज और विद्यालयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके।

भोजन से पहले विद्यार्थियों ने मंत्रोच्चार किया, इसके बाद सभी बच्चों को भोजन कराया गया तथा कॉपी और पेन का भी वितरण किया गया।

कार्यक्रम में स्कूल प्रबंधन समिति की अध्यक्ष हषिर्का संभव जैन, पार्षद प्रतिभा सुरेश गुप्ता, विकासखंड शिक्षा अधिकारी नेम सिंह साहू, शहरी स्रोत केंद्र समन्वयक डॉ. शशिभूषण शर्मा, सहायक एपीसी समग्र शिक्षा जिला दुर्ग विनोद कुमार शुक्ला सहित तीनों विद्यालयों के प्रधानपाठक, शिक्षक, अभिभावक, जन समर्पण सेवा संस्था के पदाधिकारी एवं सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आयोजन में सैकड़ों विद्यार्थियों की सहभागिता ने कार्यक्रम को सफल और प्रेरणादायी बनाया।

आकाशगंगा मंडी में नगर निगम भिलाई की कार्रवाई, सड़क बाधा और बिना लाइसेंस पर 1900 रुपये लगाया जुर्माना

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

अतिक्रमण हटाने और नियम तोड़ने वाले 8 व्यापारियों पर चला हंटर

नगर पालिक निगम भिलाई ने स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई अभियान के तहत गुरुवार को जोन-1 के वार्ड-17 स्थित आकाशगंगा मंडी क्षेत्र में सख्त कार्रवाई की। सड़क पर अतिक्रमण और बिना अनुज्ञप्ति व्यवसाय करने वाले व्यापारियों से कुल 1900 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

आयुक्त सुश्री सुरूचि सिंह और स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर निगम की टीम ने मंडी क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि कई दुकानदारों ने दुकानों के सामने सड़क पर सामान और वाहन खड़े कर आवागमन बाधित कर रखा था।

किन पर लगी कितनी पेनल्टी

सड़क बाधा शुल्कः राधेलाल चौहान, मनोज सोनकर, राजा गुप्ता सब्जी एजेंट, राजकुमार गुप्ता और फरबन आलम कपड़ा ठेला से 100-100 रुपये।

सड़क बाधा शुल्कः रामचन्द्र प्याज विक्रेता और कांडेवाला प्याज विक्रेता से 200-200 रुपये।

बिना अनुज्ञप्ति व्यवसायः धनेश कुमार साहू की मोबाइल शॉप पर 1000 रुपये का जुर्माना।

निगम की टीम ने सभी व्यापारियों को भविष्य में सड़क पर ट्रक व सामान नहीं रखने और यातायात बाधित न करने की समझाइश दी। नगर निगम ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे सार्वजनिक सड़कों पर अतिक्रमण न करें और वैध अनुज्ञप्ति लेकर ही व्यवसाय संचालित करें। निगम ने कहा कि शहर में सड़क बाधा, अतिक्रमण और नियम उल्लंघन के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

आगामी भिलाई नगर निगम चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

संगठन विस्तार और बूथ स्तर तक मजबूती पर दिया जोर

आगामी भिलाई नगर निगम चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में वैशाली नगर विधानसभा के वार्ड क्रमांक 29, वृंदा नगर में पार्टी की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश सहप्रभारी समर कुमार, प्रदेश महासचिव वदूद आलम, भिलाई नगर निगम चुनाव प्रभारी डॉ. एस.के. अग्रवाल, प्रदेश सचिव के. ज्योति, मेहरबान सिंह, वैशाली नगर विधानसभा संगठन मंत्री बलविंदर सिंह और कार्यकारी जिलाध्यक्ष जसप्रीत सिंह सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

बैठक में चुनावी रणनीति, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने, जनसंपर्क अभियान तेज करने और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने पर विस्तार से चर्चा हुई।

प्रदेश सहप्रभारी समर कुमार ने कहा कि प्रत्येक बूथ पर मजबूत टीम तैयार कर आम आदमी पार्टी को जनता के बीच सशक्त विकल्प के रूप में खड़ा किया जाएगा। उन्होंने घर-घर संपर्क अभियान चलाकर जनता के मुद्दों को उठाने का आह्वान किया। प्रदेश महासचिव वदूद आलम ने कहा कि नगर निगम चुनाव जनता की अपेक्षाओं की लड़ाई है। कार्यकर्ताओं को अनुशासन और सेवा भाव के साथ हर वार्ड और बूथ तक पार्टी को मजबूत करना होगा। चुनाव प्रभारी डॉ. एस.के. अग्रवाल ने बताया कि हर वार्ड के लिए कायर्योजना तैयार की जा रही है। बूथ समितियों का गठन, मतदाता संपर्क अभियान और वार्डवार समीक्षा के जरिए चुनावी तैयारियों को गति दी जाएगी।

कायर्कारी जिलाध्यक्ष जसप्रीत सिंह ने कहा कि पार्टी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रही है। कार्यकर्ताओं की एकजुटता और जनसंपर्क ही चुनाव में पार्टी की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। बैठक के अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ संगठन को मजबूत करने और भिलाई नगर निगम चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का संकल्प लिया।

चन्दूलाल चन्द्राकर मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं का होगा विस्तार

प्रबंध और स्वशासी समिति की बैठक में 2026-27 के लिए लिए गए कई अहम फैसले

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

कचान्दुर स्थित चन्दूलाल चन्द्राकर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की प्रबंध कारिणी समिति एवं स्वशासी समिति की ग्यारहवीं बैठक मंगलवार को महाविद्यालय सभा कक्ष में हुई। बैठक की अध्यक्षता दुर्ग संभाग आयुक्त एस.एन. राठौर ने की। कलेक्टर अभिजीत सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में महाविद्यालय और संबद्ध चिकित्सालय में सुविधाओं के विस्तार को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

इन कार्यों को मिली मंजूरी : बालिका नर्सिंग छात्रावास के तृतीय एवं चतुर्थ तल का निर्माण, कॉलेज भवनों के दरवाजे-खिड़कियों की मरम्मत, डेस्कटॉप-प्रिंटर, फर्नीचर, सफाई मशीन और स्किल लैब के

लिए मैनेकिन क्रय , अध्यापन के लिए एलईडी वॉल पैनल, इंटरेक्टिव पैनल, लेक्चर हॉल में ऑडियो सिस्टम और एम्बामिंग मशीन क्रय, चिकित्सालय भवन के सामने नवीन ओपीडी कॉम्प्लेक्स, मरीजों के परिजनों के लिए सराय, रैन बसेरा, मेडिकल स्टोर, कैंटीन युक्त सिविक एमीनिटी कॉम्प्लेक्स का निर्माण, सेंट्रल लैब, ब्लड बैंक, जीआईसीयू जैसे अति महत्वपूर्ण विभागों के लिए नए एयर कंडीशनर क्रय, फिजियोथैरेपी महाविद्यालय के लिए चिकित्सालय परिसर में स्थान उपलब्ध कराना और परिसर में बाउंड्रीवॉल संधारण, लेक्चर हॉल में फायर एग्जिट, पहुंच मार्ग मरम्मत और जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार शामिल है।

आयुक्त ने पीडब्ल्यूडी, विद्युत, पीएचई और क्रेडा विभाग के अधिकारियों को सभी निर्माण एवं मरम्मत कार्य समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में अधिष्ठाता डॉ. तृप्ति नगरिया, डॉ. पी.एम. लूका, सीएमएचओ डॉ. मनोज दानी, नगर निगम भिलाई आयुक्त सुरुचि सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी और समिति सदस्य उपस्थित थे।

तेज आवाज में डीजे बजाना पड़ा महंगा पुलिस ने वाहन सहित डीजे किया जब्त

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

रात्रि में तेज ध्वनि में डीजे बजाकर ध्वनि प्रदूषण और सार्वजनिक शांति भंग करने वालों के खिलाफ पद्मनाभपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डीजे वाहन और उपकरण जब्त कर वैधानिक कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार 16 जुलाई की रात करीब 12:30 बजे रात्रिकालीन गश्त के दौरान सिविल लाइन दुर्ग क्षेत्र में एक आयशर वाहन (क्रमांक CG 07 CZ 5690) में तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। इससे आसपास के क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण फैल रहा था और लोगों की शांति भंग हो रही थी।

मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने वाहन को रोककर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 10 के तहत कार्रवाई करते हुए आयशर वाहन एवं डीजे उपकरण जब्त कर लिए। पुलिस के अनुसार डीजे का संचालक वसीम (38 वर्ष), निवासी जलेबी चौक, भिलाई है।

पुलिस ने बताया कि सार्वजनिक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से रात्रिकालीन गश्त के दौरान यह कार्रवाई की गई। ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि ध्वनि प्रदूषण एवं कोलाहल नियंत्रण संबंधी नियमों का पालन करें तथा निर्धारित समय और मानकों के अनुरूप ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

!! न्यायालय तहसीलदार भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग !!

-:: ईश्तहार ::-

रा०प्र०क्र०/. /अ-6 वर्ष 2024-25

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक /क्रेता तुकाराम साहू पिता बिसौहा साहू निवासी कोहका, द्वारा ग्राम कोहका, प.ह.नं. 45 रा.नि.मं. द कोहका तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि ख0नं0 361 रकबा 0.020 हे० भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर विक्रेता कुमुदराम पिता सहबूराम से क्रय किया है कि उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर नामांतरण किये जाने के संबंध में आवेदन पत्र मय बैनामा की छायाप्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त संबंध में पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 27.07.2026 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 10.07.2026 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से जारी किया गया है।

अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग

-:: व्यक्तिगत सूचना ::-

(रा०प्र०क्र०/... /अ-6/वर्ष 2025-26)

प्रति,
1. मेसर्स वेद प्रकाश चोपड़ा एंड कंपनी कुरूद भिलाई भागीदार आलोक कुमार लुनिया पिता स्व. जे.के. लुनिया
निवासी - पद्मनाभपुर दुर्ग
पक्षकार- श्रीमती टी अप्पिली पति श्री तोगी रमेश
निवासी - हाउसिंग बोर्ड मिलाई तह. व जिला दुर्ग
विरूद्ध
अनावेदक-छ.ग. शासन

आपको सूचित किया जाता है इस न्यायालय का रा.प्र.क्रं. /अ-6/वर्ष 2025-26 आवेदक- श्रीमती टी अप्पिली पति श्री तोगी रमेश निवासी -हाउसिंग बोर्ड भिलाई तह. व जिला दुर्ग द्वारा ग्राम कुरूद प.ह.नं. 46 रा.नि.मं. कोहका स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नं. 1383/1 रकबा 0.014 हे. भूमि का रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर दिनांक 26/11/2019 को विक्रेता मेसर्स वेद प्रकाश चोपड़ा एंड कंपनी भागीदार आलोक कुमार लुनिया पिता स्व. जे.के. लुनिया निवासी पद्मनाभपुर दुर्ग से क्रय किया गया है, की बैनामा के आधार पर नामांतरण किये जाने बाबत् आवेदन पत्र मय बैनामा की छाया प्रति प्रस्तुत किया गया है।

अतः उपरोक्त भूमि के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 17/07/2026 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज 23/06/2026 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से जारी किया गया है।

अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर

जब इंदिरा गांधी खुद लेह पहुंची थीं और सोनम वांगयाल का तुड़वाया था अनशन

लद्दाख के अधिकारों की लड़ाई का 1984 वाला अध्याय आज फिर याद आ रहा है

नई दृष्टिबिंदु / लेह-नईदिल्ली

लद्दाख के संवैधानिक अधिकारों की मांग एक बार फिर सुर्खियों में है। प्रसिद्ध शिक्षाविद् और नवप्रवर्तक सोनम वांगचुक इन दिनों शिक्षा में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए दिल्ली में छात्रों के साथ आमरण अनशन पर हैं। उनके इस आंदोलन ने 40 साल पहले लेह में हुए एक ऐतिहासिक अनशन की याद ताजा कर दी है। वह अनशन लद्दाख के उनके पिता सोनम वांगयाल का था, जिसे खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आकर तुड़वाया था।

1984: ST दर्जे की मांग ने पकड़ा जोर

वर्ष 1984 लद्दाख के इतिहास का अहम मोड़ था। उस समय लद्दाख जम्मू-कश्मीर का हिस्सा था। स्थानीय बौद्ध बहुल समुदाय और अन्य स्वदेशी जनजातियों को लग रहा था कि उन्हें पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व, संवैधानिक सुरक्षा और विकास के अवसर नहीं मिल रहे। इसी के लिए वे अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांग रहे थे।

इस आंदोलन का नेतृत्व वरिष्ठ जननेता सोनम वांगयाल कर रहे थे। वे कई वर्षों तक जम्मू-कश्मीर विधानसभा और सरकार का हिस्सा रहे। कुशोक बकुला रिनपोछे के साथ मिलकर उन्होंने लद्दाख के विकास, सामाजिक सद्भाव और जनजातीय अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष किया। सोनम वांगयाल ने ST दर्जे की मांग को लेकर लेह में अनशन शुरू किया। यह अनशन पूरे लद्दाख में चर्चा का विषय बन गया।

इंदिरा गांधी पहुंचीं लेह

आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए

प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्वयं लेह पहुंचकर सोनम वांगयाल से मुलाकात की। उन्होंने उनकी मांगों को ध्यान से सुना और जूस का गिलास देकर उनका अनशन तुड़वाया। इसी मुलाकात में उन्होंने लद्दाख के स्वदेशी समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने का आश्वासन भी दिया।

इंदिरा गांधी सीमावर्ती क्षेत्रों की समस्याओं को गंभीरता से सुनती थीं और जरूरत पड़ने पर खुद हस्तक्षेप करती थीं। दुर्भाग्य से अक्टूबर 1984 में उनकी हत्या हो गई और उनके जीवनकाल में यह मांग पूरी नहीं हो सकी। लेकिन उनके द्वारा शुरू की गई प्रक्रिया जारी रही और अंततः 7 अक्टूबर 1989 को लद्दाख के प्रमुख समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया।

इतिहास और आज का कनेक्शन

1984 में लेह का वह अनशन सिर्फ एक विरोध नहीं था, बल्कि लद्दाख की पहचान, सम्मान और संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई का महत्वपूर्ण अध्याय था। प्रधानमंत्री का स्वयं आकर हस्तक्षेप करना इसे भारतीय राजनीतिक इतिहास में विशेष बनाता है।

आज सोनम वांगयाल के पुत्र सोनम वांगचुक उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। वे लद्दाख के लिए Sixth Schedule जैसी संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन और अनशन कर चुके हैं। अभी वह शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए दिल्ली में अनशन पर हैं।

इतिहास गवाह है कि जब लद्दाख की आवाज को गंभीरता से सुना गया, तो समाधान निकला। 1984 का वह जूस का गिलास आज भी याद दिलाता है कि संवाद और संवेदनशीलता से ही सीमांत क्षेत्रों की समस्याओं का हल संभव है।

खास खबर

रेलवे के आधुनिकीकरण से यात्री सुविधाओं, व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को मिलेगी नई गति : मुख्यमंत्री साय

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित सरोना एवं बालोद रेलवे स्टेशन का होगा शुभारंभ, मुख्यमंत्री साय से रायपुर मंडल रेल प्रबंधक दयानन्द ने की सौजन्य भेंट

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में रायपुर मंडल रेल प्रबंधक दयानन्द ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित सरोना एवं बालोद रेलवे स्टेशनों के उद्घाटन समारोह के लिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आमंत्रण पत्र भेंट किया। भेंट के दौरान अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत सरोना एवं बालोद रेलवे स्टेशनों पर विकसित आधुनिक यात्री सुविधाओं, अधोसंरचना उन्नयन तथा स्टेशनों के नए स्वरूप को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना भारतीय रेलवे को आधुनिक, सुरक्षित, सुगम और यात्री-केंद्रित बनाने की दिशा में एक दूरदर्शी पहल है, जिसका लाभ सीधे आम नागरिकों और प्रदेश के समग्र विकास को मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय रेलवे आज अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। देशभर के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं, बेहतर यात्री सेवाओं और विश्वस्तरीय अधोसंरचना से सुसज्जित किया जा रहा है, जिससे विकसित भारत के संकल्प को नई गति मिल रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे केवल आवागमन का माध्यम नहीं, बल्कि विकास, व्यापार, पर्यटन और जनसुविधाओं की जीवनरेखा है। रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरोना एवं बालोद रेलवे स्टेशनों के उन्नयन से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी तथा क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को भी नई गति प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार के समन्वित प्रयासों से छत्तीसगढ़ में आधुनिक रेल अधोसंरचना का विस्तार तेजी से हो रहा है। रेल संपर्क के सुदृढ़ होने से प्रदेश में निवेश, उद्योग, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा आम नागरिकों का आवागमन अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित बनेगा।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को वर्चुअल माध्यम से देशभर में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित एवं नवीनीकृत रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे। इस योजना का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों को आधुनिक, सुगम, सुरक्षित एवं यात्री-अनुकूल बनाकर देश की परिवहन व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है।

संतोषी नगर ब्रिज में बड़ा हादसा, ट्रक नीचे गिरा

रायपुर। राजधानी रायपुर के संतोषी नगर ब्रिज के पास शुक्रवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। तेलीबांधा से आमानाका की ओर जा रहा ट्रक (RJ 31 GB 3122) अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया और करीब 15 फीट नीचे जा गिरा। हादसे के दौरान ट्रक ने एक कार को भी टक्कर मार दी। राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रक तेज रफ्तार में था। संतोषी नगर ब्रिज के पास चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका, जिससे ट्रक पहले डिवाइडर से टकराया और फिर सड़क से नीचे जा गिरा। हादसे के दौरान वहां अफरा-तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोगों की भीड़ जुट गई। ट्रक की चपेट में आने से कार (CG 04 MA 3271) भी क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि कार सवार सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से ट्रक को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। कुछ देर तक इस मार्ग पर यातायात भी प्रभावित रहा।

शैली गुप्ता ने अंतरराष्ट्रीय मत्सोगी-डो चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक

नक्सल प्रभावित रहे सुकमा से खेल प्रतिभा की नई उड़ान

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में पहचाना जाने वाला सुकमा आज खेल, शिक्षा और युवा प्रतिभाओं के दम पर अपनी नई पहचान गढ़ रहा है। जिले की होनहार खिलाड़ी शैली गुप्ता इस परिवर्तन की मिसाल बनी हैं, जिन्होंने नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में 24 जून से 26 जून तक आयोजित अंतरराष्ट्रीय मत्सोगी-डो चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम सीनियर महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भारत, छत्तीसगढ़ और सुकमा का नाम अंतरराष्ट्रीय मंच पर गौरवान्वित किया है।

नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के खिलाड़ियों के बीच शानदार प्रदर्शन करते हुए शैली ने फाइनल मुकाबले में एकतरफा जीत दर्ज कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव और सुकमा जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने शैली की इस शानदार सफलता पर उन्हें बधाई दी है।

राज्य शासन द्वारा सुकमा में खेल अधोसंरचना के विकास, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, प्रतियोगिताओं में भागीदारी के अवसर तथा सरकार की खेल प्रोत्साहन योजनाओं का प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। दूरस्थ और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद जिले के युवा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। शैली गुप्ता की उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि सही मार्गदर्शन, प्रशासनिक सहयोग और दृढ़ संकल्प से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। अंतरराष्ट्रीय सफलता के बाद शैली गुप्ता ने अपने माता-पिता के साथ सुकमा के कलेक्टर अमित कुमार से मुलाकात की। कलेक्टर ने उन्हें बधाई देते हुए उच्च शिक्षा में प्रशासन की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।

शैली गुप्ता का स्वर्ण पदक केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि बदलते हुए सुकमा की नई तस्वीर का प्रतीक है। यह सफलता जिले के युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने की प्रेरणा देगी। शासन-प्रशासन द्वारा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की प्रतिबद्धता ने युवाओं में नया आत्मविश्वास जगाया है। राज्य शासन शिक्षा, खेल और युवा विकास के क्षेत्र में निरंतर कार्य करते हुए सुकमा सहित प्रदेशभर की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय एवं वैश्विक मंच तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार के इन कार्यों से बस्तर में विकास और उपलब्धियों को नई पहचान मिल रही है।

870 ग्राम की नन्ही सी जान को मिला नया जीवन

रायपुर। जिला अस्पताल कवर्धा ने नवजात शिशु चिकित्सा के क्षेत्र में एक और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए मानवता और चिकित्सा सेवा का प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया है। अस्पताल की स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट (एसएनसीयू) में मात्र 870 ग्राम वजन के अति समयपूर्व (एक्सट्रीम प्रीटर्म) जन्मे नवजात शिशु का सफल उपचार कर उसे स्वस्थ अवस्था में घर भेजा गया। जन्म के समय शिशु की स्थिति अत्यंत गंभीर थी और उसके जीवित रहने की संभावना बेहद कम मानी जा रही थी, लेकिन चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ के समर्पित प्रयासों ने इस नन्ही जान को नया जीवन प्रदान किया। जन्म के तुरंत बाद नवजात को जिला अस्पताल की एसएनसीयू में भर्ती किया गया, जहां शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. शलिल मिश्रा के मार्गदर्शन में डॉ. त्रिभुवन जायसवाल, चिकित्सा अधिकारी (एसएनसीयू) सहित विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ ने चौबीसों घंटे उसकी गहन निगरानी की। उपचार के दौरान नवजात को श्वसन सहायता, शरीर का तापमान नियंत्रित रखने, संक्रमण से सुरक्षा, संतुलित पोषण तथा अन्य आवश्यक नवजात गहन चिकित्सा सेवाएं लगातार उपलब्ध कराई गईं। लगभग एक माह तक चले सतत उपचार, विशेषज्ञ निगरानी और समर्पित देखभाल के परिणामस्वरूप नवजात के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हुआ। इस अवधि में उसका वजन 870 ग्राम से बढ़कर 1600 ग्राम हो गया। चिकित्सकीय परीक्षणों में पूरी तरह स्थिर पाए जाने के बाद उसे स्वस्थ अवस्था में डिस्चार्ज कर परिजनों को सौंप दिया गया।

लगाया गया हर पौधा आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का आधार बनेगा : मुख्यमंत्री साय

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

आमतौर पर एटीएम का नाम सुनते ही लोगों के मन में पैसे निकालने वाली मशीन की तस्वीर उभरती है, लेकिन जशपुर वन विभाग ने पर्यावरण संरक्षण को जन-जन का अभियान बनाने की दिशा में एक अभिनव पहल करते हुए 'ट्री एटीएम' की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बगिया हेलीपैड परिसर में इस अनूठे मोबाइल ट्री एटीएम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पहल आम नागरिकों तक पौधों की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण एवं जनजागरूकता को नई गति प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर स्वयं ट्री एटीएम से आंवला का पौधा प्राप्त किया तथा उपस्थित लोगों को भी पौधों का वितरण किया। उन्होंने कहा कि यह मोबाइल ट्री एटीएम जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर आम नागरिकों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराएगा। इससे अधिक से अधिक लोग पौधरोपण से जुड़ेंगे और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनभागीदारी को नया विस्तार मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर वन विभाग की इस अभिनव पहल की सराहना करते हुए कहा कि 'ट्री एटीएम' लोगों को सहज और सरल तरीके से पौधे उपलब्ध कराने का एक सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में वर्षा ऋतु पौधरोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय है। ऐसे समय में यह पहल लोगों को विभिन्न प्रजातियों के पौधे आसानी से उपलब्ध कराएगी, जिससे व्यापक स्तर पर पौधरोपण को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को नई मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। यदि प्रत्येक व्यक्ति एक पौधा लगाकर उसके वृक्ष बनने तक उसकी देखभाल का संकल्प ले, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, हरित और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित किया जा सकता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अधिक से अधिक पौधरोपण कर 'एक पेड़ मां के नाम' महाअभियान से जुड़ने का आह्वान किया।

उल्लेखनीय है कि 'एक पेड़ मां के नाम' महाअभियान के अंतर्गत प्रारंभ किए गए ट्री एटीएम को 'आज का पौधा, आने वाली पीढ़ियों की छांव' के प्रेरक संदेश के साथ रवाना किया गया। इस अभिनव पहल के तहत केवल निःशुल्क पौधों का वितरण ही नहीं किया जाएगा, बल्कि पौधा प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पौधरोपण की वैज्ञानिक एवं सही विधि, नियमित देखभाल, संरक्षण तथा पौधे को वृक्ष बनने तक सुरक्षित रखने के उपायों की भी जानकारी दी जाएगी। इसका उद्देश्य केवल पौधे लगाना नहीं, बल्कि उनके संरक्षण और जीवित रहने की दर को बढ़ाना है, ताकि पर्यावरण संरक्षण का यह अभियान दीर्घकालिक और प्रभावी बन सके।

धमतरी के स्कूल में एक हफ्ते तक चला 'काटने' का सिलसिला

11वीं के छात्र ने 18 सहपाठियों को दांतों से काटा, जांच में रेबीज के लक्षण नहीं मिले

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर-धमतरी

कुरूद विकासखंड के ग्राम सिलौटी स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पिछले एक सप्ताह से चली अजीब घटना ने सभी को हैरान कर दिया। यहां कक्षा 11वीं के एक छात्र ने अलग-अलग दिनों में अपने 18 सहपाठियों को दांतों से काट दिया। शुरुआत में इसे मामूली शरारत समझा गया, लेकिन पीड़ितों की संख्या बढ़ने पर स्कूल में दहशत फैल गई। इसी बीच यह चर्चा भी शुरू हो गई कि छात्र को तीन साल पहले एक आवारा कुत्ते ने काटा था।

डॉक्टरों ने खत्म किया सस्पेंस

जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. जेपी दीवान ने बताया कि छात्र में रेबीज का कोई लक्षण नहीं मिला। रेबीज में पानी से डर, तेज रोशनी-आवाज से परेशानी और व्यवहार में बदलाव जैसे लक्षण होते हैं, लेकिन जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला। 18 छात्रों में से केवल एक की पीठ पर दांत के दो हल्के निशान मिले हैं।

सीएमएचओ डॉ. यूएल कौशिक ने बताया कि तीन सात पहले कुत्ते के काटने के बाद छात्र का रेबीज टीकाकरण कोर्स पहले ही पूरा हो चुका था।

कबड्डी में हार के बाद की शरारत

काउंसलिंग में छात्र ने बताया कि कबड्डी के खेल में हारने के बाद उसने शरारतवश दोस्तों को काटा था। डॉक्टरों ने उसे मानसिक रूप से सामान्य और स्वस्थ बताया है।

अब शिक्षा विभाग और स्कूल प्रबंधन इसे अनुशासन से जोड़कर देख रहे हैं। छात्र की नियमित काउंसलिंग कराई जाएगी। प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें।

स्वास्थ्य विभाग ने कराई जांच और टीकाकरण

स्थिति गंभीर देख स्कूल प्रबंधन ने स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी। सभी 18 छात्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोर्रा में स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया और एहतियातन एंटी-रेबीज वैक्सीन लगाई गई। वहीं संबंधित छात्र को भी जिला अस्पताल भेजकर विशेषज्ञों से परीक्षण और काउंसलिंग कराई गई।

रथयात्रा हमारी आस्था, लोकसंस्कृति, सामाजिक समरसता और जनभागीदारी का जीवंत महापर्व : मुख्यमंत्री साय

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के गायत्री नगर स्थित भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर में आयोजित भव्य रथयात्रा महोत्सव में शामिल हुए। दोनों ने विधिवत पूजा-अर्चना कर भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का आशीर्वाद प्राप्त किया तथा पारंपरिक छेरा-पहरा की रस्म निभाते हुए प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर मंदिर परिसर श्रद्धालुओं की आस्था, भक्ति और उत्साह से सराबोर रहा। वैदिक मंत्रोच्चार, भजन-कीर्तन और जयघोष के बीच भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की प्रतिमाओं को विशेष विधि-विधान के साथ मंदिर से रथ तक लाया गया।

इसके पूर्व राज्यपाल रमेन डेका एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पारंपरिक रीति से सोने की झाड़ू द्वारा छेरा-पहरा की रस्म निभाकर रथमार्ग का प्रतीकात्मक शुद्धिकरण किया। इसके पश्चात

महाप्रभु की प्रतिमाओं को श्रद्धापूर्वक रथ पर विराजित किया गया और रथयात्रा का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों को रथयात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान श्री जगन्नाथ की रथयात्रा सनातन संस्कृति, सामाजिक समरसता, लोकपरंपरा और जन-जन की आस्था का महापर्व है। यह उत्सव समाज को सेवा, समर्पण, समानता और लोककल्याण का संदेश देता है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि भगवान श्री जगन्नाथ किसानों के आराध्य और अन्नदाता के रक्षक माने जाते हैं। उनकी कृपा से समय पर वर्षा होती है, खेतों में हरियाली आती है, धान की बालियों में दूध भरता है और किसानों के घरों में समृद्धि का आगमन होता है। उन्होंने भगवान श्री जगन्नाथ से प्रार्थना की कि इस वर्ष प्रदेश में भरपूर वर्षा हो, कृषि समृद्ध हो, किसानों की मेहनत सफल हो और छत्तीसगढ़ निरंतर विकास एवं खुशहाली के पथ पर आगे बढ़ता रहे।

श्री साय ने कहा कि भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का दिव्य आशीर्वाद समस्त प्रदेशवासियों पर बना रहे तथा सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का संचार हो। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन हमारी परंपराओं को सशक्त बनाने के साथ-साथ समाज में सद्भाव, एकता और सामूहिक चेतना को भी नई ऊर्जा प्रदान करते हैं।

उल्लेखनीय है कि राजधानी रायपुर के गायत्री नगर स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में प्रतिवर्ष पुरी की विश्वविख्यात रथयात्रा की तर्ज पर यह आयोजन अत्यंत श्रद्धा और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न होता है। छेरा-पहरा की परंपरा इस बात का प्रतीक है कि भगवान के समक्ष सभी समान हैं और सेवा ही सर्वोच्च धर्म है।

उल्लेखनीय है कि ओडिशा का पड़ोसी राज्य होने के कारण छत्तीसगढ़ में भगवान श्री जगन्नाथ के प्रति विशेष श्रद्धा और आस्था रही है। प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में रथयात्रा का आयोजन उत्साहपूर्वक किया जाता है। उत्कल संस्कृति और दक्षिण कोसल की सांस्कृतिक परंपराओं के बीच यह पर्व एक सशक्त सेतु का कार्य करता है। इस अवसर पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक पुरंदर मिश्रा, विभिन्न निगम-मंडलों एवं आयोगों के अध्यक्षगण, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।

संपादकीय

मांग एक है पर कांग्रेस सीजेपी का साथ नहीं दे रही

राजनीति में एक सत्ता पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है। जो सत्ता पक्ष के साथ नहीं होता है, वह विपक्ष के साथ होता है। जब भी सरकार के खिलाफ कोई बड़ा व देशव्यापी मुद्दा सामने आता है तो विपक्ष के सारे दल, सारे राजनीतिक व गैरराजनीतिक संगठन एक हो जाते है और बड़ा प्रभावी आंदोलन करते है,ऐसे बड़े व व्यापक आंदोलन का असर भी होता है,ऐसे आंदोलनों के कारण कई बार देश में सत्ता भी बदलती है,सरकार को झुकना पड़ता है,विपक्षी दलों व गैरराजनीतिक संगठनों की मांग को मानना पड़ता है। काकरोच जनता पार्टी एक ऐसा ही संगठन है जो नीट पेपर लीक के मामले में सरकार से मांग कर रहा है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया जाए। कांग्रेस भी नीट पेपर लीक को लेकर मांग कर रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। सीजेपी ने जंतर मंतर में इस मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, इसे दो तीन सप्ताह हो गए हैं, सीजेपी की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 18 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं। विपक्ष के कई नेताओं ने सरकार के बात न करने को लेकर वांगचुक से अपील की है वह अपना अनशन समाप्त कर दें। लेकिन कांग्रेस ने अब तक सीजेपी के आंदोलन को लेकर एक शब्द समर्थन मे नहीं कहा है जबकि दोनों की मांग एक है कि शिक्षा मंत्री प्रधान इस्तीफा दें।

सीजेपी एक जज की टिप्पणी के विरोध में बना संगठन है, इसके नेता को सोशल मीडिया में मिल रहे समर्थन से वहम हो गया था कि वह किसी ऐतिहासिक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। लाखों लोगों ने संगठन का समर्थन किया तो लगा कि उनका आंदोलन सफल हो गया है ।उन्होंने मान लिया कि वह जंतर मंतर में धरना देंगे तो देश भर से लाखों युवा उनके धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे, विपक्ष उनका समर्थन करने को मजबूर होगा और सरकार को उनकी मांग माननी पड़ेगी। सीजेपी का जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन को 18 दिन से ज्यादा हो गए हैं, एक भी विपक्ष का बड़ा नेता ने जैसे राहुल गांधी जंतर मंतर पर जाकर उनके साथ खड़ा नहीं हुआ है। हां सोशल मीडिया के जरिए समर्थन जरूर कुछ नेता कर रहे हैं।सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके वांगचुक की जगह भूख हड़ताल करते तो युवाओं पर उसका ज्यादा असर होता उनके सामने नहीं आने का फायदा वांगचुक ने उठाया है और वह पहले भी भूख हड़ताल करते रहे हैं और जानते हैं कि भूख हड़ताल करने पर उनका खूब प्रचार होगा। यही हो रहा है अभी अभिजीत दीपके की चर्चा कम वागंचुक की चर्चा ज्यादा हो रही है। नेता अभिजीत हैं लेकिन नेता के रूप में प्रचारित तो वांगचुक हो रहे हैं, विपक्ष अनशन करने पर उनकी चिंता कर रहा है। अभिजीत को मजबूरी मे वांगचुक का साथ लेना पड़ रहा है क्योंकि सीजेपी का धरना प्रदर्शन में तो लोगों की भीड़ जुट नहीं रही है लेकिन वांगचुक के अनशन के कारण सीजेपी चर्चा में तो है।

सवाल उठता है कांग्रेस नेता राहुल गांधी सीजेपी व वांगचुक के अनशन को लेकर चुप क्यों है क्योंकि वह तो नेता प्रतिपक्ष है, उनको तो विपक्ष के हर नेता के आंदोलन का समर्थन मौके पर जाकर करना चाहिए ।विपक्ष के कई नेता कह भी रहे हैं कि राहुल गांधी को जंतर मंतर जाकर सीजेपी और वांगचुक के अनशन का समर्थन करना चाहिए। राहुल गांधी खुद भी गूंज के जरिए इसी मुद्दे पर छात्रों के बीच जाकर नीट पेपर लीक व प्रधान के इस्तीफे पर जोर दे रहे हैं यानी राहुल गांधी खुद को जेन जी के नेता के रूप में स्थापित करना चाहते है और बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसा जेन जी आंदोलन नीट पेपर लीक व प्रधान के इस्तीफे को लेकर करना चाहते हैं। राहुल गांधी तो कई महीनो से सपना देख रहे हैं कि भारत का जेन भी किसी मुद्दे पर तो आंदोलन करे और उनको भाजपा व मोदी को सत्ता से हटाने का मौका मिले। लेकिन महीनों बाद भी भारत के जेन जी ने ऐसा कुछ नहीं किया है।

नीट पेपर लीक हुआ तो राहुल गांधी को लगा अब मौका आया है जेन जी जरूर देश में ऐसा आंदोलन करेगा कि मोदी सरकार मुश्किल में पड़ जाएगी ।वह छात्रों के बीच जाकर मोदी सरकार के खिलाफ माहौल भी बना रहे थे लेकिन अभिजीत दीपके ने नीट पेपर लीक को लेकर सीजेपी का गठन कर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। अभिजीत दीपके युवाओं का नेता बन गया, उसे सोशल मीडिया में लाखों लोगों का समर्थन मिलने लगा। इससे राहुल गांधी के जेन जी का अकेला नेता बनने के रास्ता बंद हो गया क्योंकि अभिजीत भी तो जेन जी का ही नेता है। एक आंदोलन का एक नेता हो सकता है, यही वजह है राहुल गांधी अभिजीत दीपके व सीजेपी का समर्थन नहीं कर रहे है। वह अलग से अपना आंदोलन चला रहे हैं। राहुल गांधी व कांग्रेस को डर है कि यदि कांग्रेस व राहुल गांधी अभिजित दीपके के आंदोलन का समर्थन करते हैं तो वह बड़ा नेता बनकर राहुल गांधी व कांग्रेस को ही भविष्य में नुकसान पहुंचा सकता है जैसा अन्ना आंदोलन से निकले आमआदमी पार्टी ने नुकसान पहुंचाया था।

सब जानते हैं कि अन्ना आंदोलन इसलिए सफल हुआ था,अन्ना एक बड़े साफसुथरी छबि के ईमानदार नेता थे,कई आंदोलन कर चुके थे और सरकार का उनकी बात माननी पड़ती थी। उनका आंदोलन भ्रष्टाचार जैसे बड़े मुद्दे को लेकर था और देश विदेश से उनको इसके लिए समर्थन मिला था। उन्होंने भी अनशन किया था,उनके अनशन का असर हुआ था,तब के विपक्ष भाजपा ने यूपीए सरकार के खिलाफ अन्नाआंदोलन का पूरा समर्थन किया था और इसी आंदोलन के असर के कारण यूपीए की चुनाव में हार हुई थी और २०१४ का चुनाव भाजपा जीती थी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी ।वांगचुक अन्ना हजारे नहीं है,उनको पूरे देश में कोई जानता नहीं है। अभिजीत दीपके भी कोई जमीन से जुड़े नेता नहीं है, वर्तमान की प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस उसके साथ खड़ी नहीं हो रही है इसलिए सीजेपी के आंदोलन व वांगचुक के अनशन असर देश पर कोई खास नहीं पड़ा है। दिल्ली में कोई आंदोलन तब ही सफल होता है जब दिल्ली सहित आसपास के राज्यों से लोगों की भीड़ जुटती है। सीजेपी के आंदोलन में दिल्ली के लोग ही नहीं आ रहे हैं। इससे भी आंदोलन बडा आंदोलन बन नहीं रहा है और माना भी नहीं जा रहा।

सरकारी विज्ञापन और मीडिया की अर्थव्यवस्था!

देवेन्द्र किशोर गुप्ता

छत्तीसगढ़ विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने जनवरी 2024 से मार्च 2026 के बीच यानी सवा दो सालों में प्रचार-प्रसार और विज्ञापनों पर 1,095 करोड़ से अधिक खर्च किए हैं। इस राशि में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और फील्ड पब्लिसिटी पर किया गया व्यय शामिल है। इस खुलासे के बाद विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं और इसे फिजूलखर्ची बताया है। लेकिन राजनीति में स्मृति अक्सर बहुत छोटी होती है।

सरकारी विज्ञापनों पर सियासत करिए पर पत्रकारों का पक्ष भी समझिए!

आज जो कांग्रेस वर्तमान सरकार के विज्ञापन खर्च को मुद्दा बना रही है, उसके अपने शासनकाल के दौरान भी विज्ञापन पर बड़े पैमाने पर सरकारी धन खर्च हुआ। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल के अंतिम सात महीनों में 750 करोड़ से ज्यादा खर्च किया गया। सीजी खबर के अनुसार उन 7 महीनों में सरकार औसतन प्रतिदिन लगभग 2.74 करोड़ विज्ञापनों पर खर्च कर रही थी। यही नहीं, विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में यह दावा भी सामने आया कि उनके पूरे कार्यकाल में संवाद एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से लगभग 3,000 करोड़ खर्च किए गए। फेसबुक, ट्विटर (अब एक्स), डिजिटल प्लेटफॉर्म, राष्ट्रीय मीडिया, यहां तक कि नेपाली टेलीविजन चैनलों और दिल्ली एयरपोर्ट पर लगे विज्ञापन भी उस समय चर्चा का विषय रहे।

इसमें मजेदार बात ये भी है कि चुनावी वर्ष के सरकारी प्रचार की ज्यादातर राशि का मीडिया को भुगतान आने वाली सरकार करती है। जैसे डॉ रमन सिंह के कार्यकाल के लगभग 100 करोड़ का भुगतान भूपेश बघेल के कार्यकाल में हुआ उसी तरह भूपेश बघेल की सरकार का लगभग सवा करोड़ भुगतान विष्णुदेव साय की सरकार में हुआ।

यदि इन तथ्यों को साथ रखकर देखा जाए तो स्पष्ट है कि विज्ञापन केवल किसी एक सरकार की नीति नहीं रही हैं। सत्ता में चाहे कोई भी दल रहा हो, हर सरकार ने अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए विज्ञापन का सहारा लिया है। इसलिए बहस केवल इस बात पर नहीं होनी चाहिए कि किसने कितना खर्च किया, बल्कि इस पर होनी चाहिए कि खर्च कितना पारदर्शी, न्यायसंगत और जनहितकारी था। लेकिन इस पूरी बहस का एक पक्ष ऐसा है, जिसकी चर्चा सबसे कम होती है। पत्रकारों और मीडिया कर्मियों का पक्ष।

सरकारी विज्ञापन केवल सरकार का प्रचार नहीं हैं। यही विज्ञापन प्रदेश के सैकड़ों समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, क्षेत्रीय चैनलों, डिजिटल पोर्टलों और हजारों श्रमजीवी पत्रकारों की आर्थिक रीढ़ भी हैं। इन्हीं से रिपोर्टरों का मानदेय निकलता है, फोटोग्राफरों को काम मिलता है, कैमरामैन, वीडियो एडिटर, डिजाइनर, प्रिंटिंग प्रेस, वितरण व्यवस्था और मीडिया संस्थानों से जुड़े हजारों परिवारों का घर चलता है। यह भी याद रखना चाहिए कि पत्रकार भी इसी समाज के नागरिक हैं। उनका भी परिवार है, बच्चों की शिक्षा है, स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं हैं और जीवनयापन की चुनौतियां हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों से हर दिन जवाबदेही की अपेक्षा की जाती है, लेकिन उनके प्रति सरकार और समाज की जिम्मेदारियों पर बहुत कम चर्चा होती है।

सरकारें किसानों, महिलाओं, युवाओं, विद्यार्थियों मजदूरों, उद्योगों और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं पर हजारों करोड़ रुपये खर्च करती हैं। यह आवश्यक भी है। लेकिन पत्रकारों के कल्याण पर होने वाला प्रत्यक्ष खर्च इसकी तुलना में बहुत सीमित है या यू कहे न के बराबर है। ऐसे में सरकारी विज्ञापन केवल प्रचार का माध्यम नहीं, बल्कि मीडिया उद्योग की आर्थिक स्थिरता का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन जाते हैं।

परंतु इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि विज्ञापन बिना नियमों के बांटे जाएं। सरकार का दायित्व है कि विज्ञापन वितरण पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित हो। किसी मीडिया संस्थान को उसकी विचारधारा या सरकार के प्रति उसके रुख के आधार पर न पुरस्कृत किया जाए और न ही दंडित। छोटे और मध्यम समाचार पत्रों, ग्रामीण पत्रकारिता और क्षेत्रीय मीडिया को भी न्यायसंगत अवसर मिलना चाहिए। लोकतंत्र में सरकार की योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाना भी आवश्यक है और सरकार से सवाल पूछना भी उतना ही आवश्यक है। इन दोनों जिम्मेदारियों के बीच पत्रकारिता एक सेतु का काम करती है। यदि पत्रकारिता आर्थिक रूप से कमजोर होगी तो लोकतंत्र भी कमजोर होगा।

इसलिए सरकारी विज्ञापनों पर होने वाली बहस केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। बहस इस बात पर होनी चाहिए कि विज्ञापन नीति कैसी हो, पत्रकारों का भविष्य कैसे सुरक्षित हो और मीडिया संस्थानों को निष्पक्ष अवसर कैसे मिले। सरकारें बदलती रहेंगी, विपक्ष भी बदलता रहेगा। लेकिन पत्रकारिता लोकतंत्र का स्थायी स्तंभ है। मजबूत सरकारें लोकतंत्र को चलाती हैं, जबकि मजबूत और स्वतंत्र पत्रकारिता लोकतंत्र को जीवित रखती है। इसलिए विज्ञापन पर राजनीति कीजिए, लेकिन पत्रकारिता के पक्ष को भी नजरअंदाज मत कीजिए।

हमारी भाषाएँ मर रही हैं, हम अंग्रेजी में उनका श्राद्ध कर रहे हैं

आरके जैन

सुप्रीम कोर्ट का हालिया प्रश्न — क्या अंग्रेजी को भारत की स्वदेशी भाषा माना जा सकता है?—सिर्फ न्यायालय का सवाल नहीं, भारत की भाषाई चेतना पर दस्तक है। यह बहस अंग्रेजी के पक्ष-विपक्ष की नहीं, उस मानसिकता की है जिसने आजादी के आठ दशक बाद भी भाषा को आत्मसम्मान नहीं, हैसियत का पैमाना बना रखा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आई अंग्रेजी आज विश्वविद्यालयों, न्यायालयों, प्रशासन, विज्ञान, तकनीक और कॉरपोरेट जगत की प्रमुख भाषा है। करोड़ों भारतीय इसे शिक्षा और रोजगार का माध्यम बना चुके हैं, इसलिए इसे पूरी तरह विदेशी कहना यथार्थ से मुंह मोड़ना होगा। पर क्या लंबे उपयोग से कोई भाषा स्वदेशी हो जाती है? यदि हाँ, तो स्वदेशी का आधार इतिहास होगा, संस्कृति या सुविधा? सुप्रीम कोर्ट ने भाषा नहीं, भारतीय आत्मविश्वास का प्रश्न उठाया है। वही आत्मविश्वास जिसने कभी संस्कृत, पाली, प्राकृत, तमिल, हिंदी, बंगाली, मराठी, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, असमिया और सैकड़ों बोलियों के बल पर विश्व को ज्ञान दिया, लेकिन आज अपने ही देश में स्वयं को सिद्ध करने के लिए विदेशी भाषा का सहारा खोजता है।

इस प्रश्न का सबसे बड़ा कटघरा हमारी न्याय व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद 348 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अधिकांश उच्च न्यायालयों की कार्यवाही व निर्णय आज भी अंग्रेजी में होते हैं। विडंबना यह है कि न्याय उसी नागरिक के लिए लिखा जाता है, जो उसकी भाषा नहीं समझता। स्वयं न्यायालय भी मान चुका है कि फैसलों और आदेशों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद आवश्यक है, क्योंकि न्याय तभी सार्थक है, जब वह जनता की भाषा में पहुंचे। फिर भी अदालतों में अंग्रेजी का प्रभुत्व निर्विवाद है। लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ यदि जनता की भाषा से दूर रहेगा, तो न्याय और नागरिक के बीच दूरी बनी रहेगी। क्या केवल वर्षों के प्रयोग से अंग्रेजी स्वदेशी हो जाएगी, या न्याय व्यवस्था को भारतीय भाषाओं से जोड़ना ही लोकतांत्रिक सुधार होगा? यह प्रश्न केवल भाषा का नहीं, न्याय तक समान पहुंच का है।

आज का सबसे कठोर सत्य यह है कि अंग्रेजी भारत में केवल भाषा नहीं, वर्गीय शक्ति का प्रतीक बन चुकी है। यही भाषा कुछ के लिए अवसरों का द्वार है, तो लाखों के लिए अदृश्य दीवार। महंगे विद्यालय, आईआईटी, आईआईएम, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और वैश्विक संस्थाएं इसे योग्यता की पहली शर्त मानती हैं। वहीं गांव का प्रतिभाशाली विद्यार्थी, दलित-बहुजन युवा और मातृभाषा में शिक्षित लाखों छात्र क्षमता नहीं, भाषा की बाधा से पीछे छूट जाते हैं। तीन-भाषा नीति पर वर्षों से जारी बहस और दक्षिण भारत का प्रतिरोध इसी भाषाई वर्चस्व की आशंका का संकेत है। यदि अंग्रेजी को स्वदेशी मान लेने से यह

असमानता और गहरी होती है, तो क्या हम नई गुलामी को ही वैधता नहीं दे रहे? कभी सत्ता तलवार से चलती थी, आज भाषा के प्रमाणपत्र से चलती है।

इतिहास इस बहस का सबसे ईमानदार साक्षी है। 1835 में लॉर्ड मैकॉले ने स्पष्ट लिखा था कि उसका उद्देश्य ऐसे भारतीय तैयार करना है, जो रक्त और रंग से भारतीय, लेकिन विचार, नैतिकता, रुचि और बुद्धि से अंग्रेज हों। यह केवल शिक्षा नीति नहीं, मानसिक उपनिवेश की योजना थी। स्वतंत्र भारत ने राजनीतिक आजादी तो पा ली, पर भाषाई स्वाधीनता का संघर्ष अधूरा रह गया। समय के साथ अंग्रेजी का स्वरूप भी बदला है। आज हिंग्लिश, तम्लिश, बेंग्लिश जैसी मिश्रित भाषाएं बताती हैं कि भारत हर भाषा को अपना रंग दे सकता है। अंग्रेजी भी अब भारतीय अनुभवों से समृद्ध है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या यह बदलाव हमारी 22 अनुसूचित भाषाओं और सैकड़ों बोलियों की कीमत पर हो रहा है? यदि नई पीढ़ी मातृभाषा से पहले अंग्रेजी में सोचने लगे, तो यह केवल भाषा का नहीं, सांस्कृतिक स्मृति के क्षरण का संकेत होगा।

दुनिया का अनुभव भारत को स्पष्ट संकेत देता है। जापान ने जापानी, जर्मनी ने जर्मन, फ्रांस ने फ्रांसीसी, चीन ने मंदारिन और इजराइल ने पुनर्जीवित हिब्रू के बल पर ज्ञान, विज्ञान और राष्ट्रीय पहचान को सशक्त बनाया। इन देशों ने अंग्रेजी सीखी, उसका उपयोग किया, लेकिन उसे अपनी पहचान पर हावी नहीं होने दिया। भारत का मार्ग टकराव नहीं, संतुलन का होना चाहिए। नई शिक्षा नीति मातृभाषा आधारित शिक्षा पर बल देती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुवाद, भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दावली, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, विधि की पढ़ाई और बहुभाषी डिजिटल ज्ञान-संसाधन बताते हैं कि ज्ञान अब अंग्रेजी की कैद में नहीं है। फिर अंग्रेजी को स्वदेशी घोषित करने की जल्दबाजी क्यों? असली चुनौती अंग्रेजी को हटाना नहीं, भारतीय भाषाओं को उस स्तर तक पहुंचाना है, जहाँ किसी विद्यार्थी का भविष्य उसकी भाषा नहीं, प्रतिभा तय करे।

यहीं सुप्रीम कोर्ट का प्रश्न सबसे अधिक दूरदर्शी बन जाता है। यह हिंदी बनाम अंग्रेजी, उत्तर बनाम दक्षिण या किसी भाषा की श्रेष्ठता का विवाद नहीं, उस भारत की खोज है जहाँ हर बच्चा मातृभाषा में सोच सके, क्षेत्रीय भाषा से समाज से जुड़े और अंग्रेजी के माध्यम से दुनिया से संवाद करे। यही बहुभाषिक भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि अंग्रेजी को स्वदेशी कहकर भारतीय भाषाओं की उपेक्षा हुई, तो लोकगीत, लोककथाएं, दर्शन, लोकविज्ञान, क्षेत्रीय साहित्य और हजारों वर्षों की सांस्कृतिक स्मृतियां हाशिए पर चली जाएंगी। लेकिन यदि अंग्रेजी वैश्विक अवसरों की भाषा और भारतीय भाषाएं राष्ट्रीय जीवन की आत्मा बनें, तो वे प्रतिद्वंद्वी नहीं, परस्पर सहयोगी होंगी। भाषा का भविष्य प्रतिस्पर्धा नहीं, सह-अस्तित्व सुरक्षित करेगा।

दरअसल, सबसे बड़ा भ्रम यही है कि स्वदेशी का अर्थ केवल उत्पत्ति से है। भारत का इतिहास बताता है कि उसने अनेक संस्कृतियों, विचारों और भाषाओं को अपनाया, पर अपनी आत्मा कभी नहीं खोई। इसलिए न अंग्रेजी का विरोध समाधान है, न महिमामंडन। असली प्रश्न यह है कि निर्णय, ज्ञान और आने वाली पीढ़ी के सपनों की भाषा कौन होगी। यदि प्रशासन, न्याय, विज्ञान, चिकित्सा, शोध और तकनीकी शिक्षा भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी, तो अंग्रेजी कभी चुनौती नहीं बनेगी। लेकिन यदि भारतीय भाषाएं घर, कविता और उत्सव तक सिमट गईं, और अंग्रेजी सत्ता, ज्ञान व अवसर की भाषा बन गई, तो वही मानसिक असमानता लौटेगी, जिसकी नींव औपनिवेशिक शासन ने रखी थी। गुलामी केवल विदेशी शासन से नहीं आती, वह तब भी आती है, जब कोई समाज अपनी भाषा पर विश्वास खो देता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कोई भाषाई निर्णय नहीं दिया, बल्कि भारत के सामने एक मूल प्रश्न रख दिया—क्या भाषा केवल सुविधा का माध्यम होगी या राष्ट्रीय आत्मविश्वास का आधार? अंग्रेजी वैश्विक अवसरों का द्वार है, लेकिन भारत की सभ्यता, लोकज्ञान, संवेदना और सांस्कृतिक चेतना भारतीय भाषाओं में ही जीवित हैं। इसलिए न अंग्रेजी का विरोध समाधान है, न उसे स्वदेशी मानकर भारतीय भाषाओं का विकल्प बनाना। आवश्यकता ऐसी व्यवस्था की है, जहाँ न्याय जनता की भाषा में मिले, शिक्षा मातृभाषा में विकसित हो, तकनीक हर भारतीय भाषा को समान अवसर दे और अंग्रेजी दुनिया से संवाद का सेतु बने, प्रभुत्व का नहीं। अंततः यह बहस अंग्रेजी की नहीं, भारत के भाषाई आत्मविश्वास की है। जो राष्ट्र अपनी भाषाओं को सम्मान देता है, वही अपने ज्ञान, संस्कृति और भविष्य को भी सुरक्षित रखता है। भारत की वास्तविक भाषाई स्वतंत्रता अंग्रेजी को स्वदेशी सिद्ध करने में नहीं, बल्कि भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय जीवन का स्वाभाविक आधार बनाने में है।

क्या भारत विरोध ने पाकिस्तान को आर्थिक संकट में धकेला?

महेन्द्र तिवारी

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के राजनीतिक सलाहकार राणा सनाउल्लाह का हालिया बयान दक्षिण एशिया की राजनीति में व्यापक चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि यदि पाकिस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अंधे विरोध की नीति न अपनाता और भारत के साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ता, तो आज पाकिस्तान को कर्ज के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ता। उन्होंने यह भी कहा कि भारत से मैत्रीपूर्ण संबंध होते तो पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता का वातावरण बनता। किसी वरिष्ठ पाकिस्तानी नेता की ओर से इस प्रकार का आत्मविश्लेषण असामान्य माना जा रहा है क्योंकि दशकों से पाकिस्तान की राजनीतिक और सामरिक सोच का बड़ा हिस्सा भारत विरोध पर आधारित रहा है।

राणा सनाउल्लाह ने अपने बयान में वर्ष 2015 का उल्लेख किया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक लाहौर पहुंचे थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। उस समय इसे दोनों देशों के संबंधों में नई शुरुआत की संभावना के रूप में देखा गया था। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद पठानकोट आतंकी हमला हुआ और उसके बाद दोनों देशों के संबंध फिर से तनावपूर्ण हो गए। राणा सनाउल्लाह का कहना है कि पाकिस्तान उस अवसर का लाभ उठाने में विफल रहा और इसके लिए स्वयं पाकिस्तान की राजनीतिक सोच तथा भारत विरोधी दृष्टिकोण जिम्मेदार रहा।

भारत और पाकिस्तान के संबंधों का इतिहास विभाजन के समय से ही जटिल रहा है। दोनों देशों ने अनेक युद्ध देखे, सीमा पर लगातार तनाव बना रहा और आतंकवाद के मुद्दे ने विश्वास की कमी को और गहरा किया। कश्मीर विवाद ने भी संबंधों को सामान्य होने नहीं दिया। समय समय पर शांति वार्ताएं हुई, व्यापार बढ़ाने के प्रयास किए गए और सांस्कृतिक आदान प्रदान की पहल भी हुई, लेकिन हर बार कोई न कोई घटना संबंधों को पीछे धकेल देती रही। इस पृष्ठभूमि में किसी पाकिस्तानी वरिष्ठ नेता द्वारा यह स्वीकार करना कि अवसर गंवाया गया, अपने आप में महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत माना जा रहा है।

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पिछले कई वर्षों से गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, बढ़ता राजकोषीय घाटा, महंगाई, ऊर्जा संकट और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से बार बार सहायता लेने की मजबूरी ने उसकी आर्थिक स्थिति को कमजोर किया है। अनेक विशेषज्ञ लंबे समय से यह तर्क देते रहे हैं कि यदि दक्षिण एशिया में आर्थिक सहयोग बढ़े और भारत तथा पाकिस्तान के बीच व्यापार सामान्य हो, तो दोनों देशों को लाभ मिल सकता है। भारत विशाल बाजार है और पाकिस्तान की कई वस्तुओं के लिए निकटतम व्यापारिक साझेदार भी हो सकता है। इसी संदर्भ में राणा सनाउल्लाह का बयान आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भारत ने पिछले एक दशक में अपनी अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना, डिजिटल भुगतान प्रणाली, विनिर्माण और वैश्विक कूटनीति में उल्लेखनीय विस्तार किया है। दूसरी ओर पाकिस्तान आर्थिक संकटों, राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से जूझता रहा है। यदि दोनों देशों के बीच सामान्य व्यापारिक संबंध होते तो सीमा पार व्यापार, परिवहन, ऊर्जा सहयोग और निवेश के नए अवसर विकसित हो सकते थे। दक्षिण एशिया विश्व की सबसे कम आर्थिक रूप से एकीकृत क्षेत्रों में गिना जाता है। इसका एक बड़ा कारण भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंध भी हैं।

राणा सनाउल्लाह ने यह भी संकेत दिया कि आज पाकिस्तान भारत से संवाद स्थापित करने के लिए विभिन्न माध्यमों का सहारा लेने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने स्वीकार किया कि दोनों देशों के बीच बैक चैनल संपर्क पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि वतर्मान परिस्थितियों में विश्वास की कमी बहुत अधिक है और पहले की तुलना में संवाद स्थापित करना कहीं अधिक कठिन हो गया है।

भारत का दृष्टिकोण भी पिछले कुछ वर्षों में अधिक स्पष्ट और कठोर हुआ है। भारत लगातार यह कहता रहा है कि आतंकवाद और वार्ता एक साथ नहीं चल सकते। भारत का आधिकारिक रुख यह है कि जब तक सीमा पार आतंकवाद समाप्त नहीं होता, तब तक संबंधों का सामान्य होना कठिन है। इसी कारण व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और उच्च स्तरीय राजनीतिक संवाद भी सीमित रहे हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच कई तनावपूर्ण घटनाओं ने इस दूरी को और बढ़ाया है।

राणा सनाउल्लाह का बयान केवल भारत की प्रशंसा भर नहीं है बल्कि पाकिस्तान की घरेलू राजनीति पर भी टिप्पणी माना जा रहा है। पाकिस्तान में लंबे समय से यह बहस चलती रही है कि राष्ट्रीय संसाधनों का बड़ा हिस्सा सुरक्षा और रक्षा आवश्यकताओं पर खर्च होता है जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पाते। यदि क्षेत्रीय तनाव कम हो तो संसाधनों का बेहतर उपयोग विकास कार्यों में किया जा सकता है। इस दृष्टि से उनका बयान पाकिस्तान के भीतर चल रही व्यापक बहस को भी सामने लाता है।

दक्षिण एशिया विश्व की लगभग एक चौथाई आबादी का घर है, लेकिन आर्थिक सहयोग के मामले में यह क्षेत्र अपेक्षाकृत पीछे है। यदि भारत और पाकिस्तान के बीच सामान्य संबंध स्थापित हों तो क्षेत्रीय व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा, जल प्रबंधन, परिवहन और शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। दोनों देशों की सांस्कृतिक विरासत, भाषाई समानता और ऐतिहासिक संबंध भी सहयोग को मजबूत आधार दे सकते हैं। यही कारण है कि समय समय पर विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी दोनों देशों के बीच संवाद बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देती रही हैं।

हालांकि केवल राजनीतिक इच्छा पर्याप्त नहीं होती। दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली के लिए ठोस कदम आवश्यक हैं। सीमा पर शांति बनाए रखना, आतंकवाद पर प्रभावी कार्रवाई, मानवीय मुद्दों का समाधान, मछुआरों और कैदियों की रिहाई, व्यापारिक प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढील और सांस्कृतिक संपर्क बढ़ाना ऐसे उपाय हो सकते हैं जो धीरे धीरे विश्वास का वातावरण तैयार करें। लेकिन यह प्रक्रिया लंबी और जटिल होगी क्योंकि दोनों देशों के बीच कई दशकों का अविश्वास मौजूद है।

राणा सनाउल्लाह के बयान पर पाकिस्तान के भीतर भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ लोगों ने इसे यथार्थवादी स्वीकारोक्ति बताया, जबकि कुछ ने इसे राजनीतिक बयानबाजी माना। भारत में भी इस बयान को सावधानी के साथ देखा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी सकारात्मक परिवर्तन का आकलन केवल बयानों से नहीं बल्कि व्यवहारिक कदमों से किया जाना चाहिए। जब तक दोनों देशों की नीतियों में ठोस बदलाव दिखाई नहीं देता, तब तक ऐसे वक्तव्यों को संभावनाओं के संकेत के रूप में ही देखा जाएगा।

इतिहास यह बताता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार सकारात्मक पहल हुई है। बस सेवा शुरू हुई, व्यापार बढ़ाने की कोशिश हुई, खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के बीच संपर्क भी बढ़ा। लेकिन हर बार किसी बड़ी सुरक्षा घटना ने इन प्रयासों को झटका दिया। इसलिए भविष्य में यदि कोई नई शुरुआत होती है तो उसे अधिक मजबूत संस्थागत आधार और पारस्परिक विश्वास की आवश्यकता होगी।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि राणा सनाउल्लाह का बयान पाकिस्तान सरकार की किसी नई आधिकारिक नीति की घोषणा नहीं है। यह एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता का सार्वजनिक आकलन है, जिसे व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। फिर भी यह इस बात का संकेत अवश्य देता है कि पाकिस्तान के भीतर कुछ राजनीतिक वर्ग अब यह स्वीकार करने लगे हैं कि लगातार टकराव की नीति से अपेक्षित लाभ नहीं मिला और आर्थिक विकास के लिए पड़ोसी देशों के साथ सहयोग आवश्यक हो सकता है।

दक्षिण एशिया की स्थिरता केवल भारत और पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। यदि दोनों देशों के बीच तनाव कम होता है तो निवेश बढ़ सकता है, व्यापारिक मार्ग खुल सकते हैं, ऊर्जा सहयोग को गति मिल सकती है और करोड़ों लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी ओर यदि अविश्वास और संघर्ष की स्थिति बनी रहती है तो विकास की संभावनाएं सीमित ही रहेंगी।

राणा सनाउल्लाह का वक्तव्य इसी व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यह अतीत की नीतियों पर आत्मचिंतन का संकेत भी है और भविष्य की संभावनाओं की ओर इशारा भी। हालांकि वास्तविक परिवर्तन केवल शब्दों से नहीं बल्कि ठोस नीतिगत निणर्यों, विश्वास निर्माण के उपायों और निरंतर संवाद से ही संभव होगा। यदि दोनों देश अपने मतभेदों को नियंत्रित

सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने पुख्ता उपाय सुनिश्चित करें : कलेक्टर मिश्रा

नई दृष्टिबिंदु / बालोद

डौण्डीलोहारा विकासखण्ड में स्वास्थ्य और महिला व बाल विकास विभाग के कार्यों की गहन समीक्षा की

कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी-कर्मचारियों को सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु पुख्ता उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डौण्डीलोहारा के सभाकक्ष में विकासखण्ड के स्वास्थ्य एवं महिला एवं बाल विकासविभाग के अधिकारी-कर्मचारियों की बैठक लेकर उक्ताशय के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना शासन के विशेष प्राथमिकता में शामिल है। इसलिए स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में बिल्कुल भी लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी। बैठक में उन्होंने डौण्डीलोहारा विकासखण्ड में विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की भी विस्तृत समीक्षा की। श्रीमती मिश्रा ने डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के कुछ उप स्वास्थ्य केन्द्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति संतोषप्रद नही पाए जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने इसके लिए संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों का वेतन रोकने के भी निर्देश दिए। बैठक में श्रीमती मिश्रा ने महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए विभाग के अधिकारियों को कुपोषण मुक्ति हेतु जरूरी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को आंगनबाड़ी केन्द्रों को कुपोषण मुक्त आंगनबाड़ी बनाने के लिए समुचित उपाय करने को कहा। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील चंद्रवंशी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जेएल उइके, जिला कार्यक्रम अधिकारी अमित सिन्हा, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के कार्यों में मेरा विशेष फोकस रहेगा। उन्होंने कहा कि जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु वे नियमित रूप से विकासखण्ड मुख्यालयों में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा करेंगे। बैठक में श्रीमती मिश्रा ने उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रवार टीकाकरण अभियान, टीबी मुक्त अभियान के अलावा संस्थागत प्रसव की स्थिति तथा कुष्ठ रोग की रोकथाम की उपाय सुनिश्चित करने हेतु किए जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु टीकाकरण कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की।

उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी-कर्मचारियों को 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी बालिकाओं को शत प्रतिशत सर्वाइकल कैंसर के बचाव हेतु टीका लगाने के निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने शिक्षक-पालक समिति बैठकों में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराकर बच्चों के पालकों को इसके लिए प्रेरित करने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में आम नागरिकों एवं मरीजों के बीपी, शुगर एवं मानसिक स्वास्थ्य, मुँह का कैंसर आदि बीमारियों का नियमित रूप से जांच की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में श्रीमती मिश्रा ने डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के बेहतर संस्थागत प्रसव वाले स्वास्थ्य केन्द्र के अधिकारी-कर्मचारियों के कार्यों की सराहना भी की। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को विभाग के बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय बालोद में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित करने हेतु प्रस्ताव भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

बैठक में श्रीमती मिश्रा ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों के अंतर्गत अधो संरचना से जुड़े कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से जर्जर एवं मरम्मत योग्य अस्पताल भवनों के अलावा अन्य जरूरी आवश्यकता के संबंध में जानकारी ली। श्रीमती मिश्रा ने जर्जर स्वास्थ्य केन्द्रों के स्थान पर नवीन भवन निर्माण तथा मरम्मत आदि आवश्यकता होने पर तत्काल प्रस्ताव भेजने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने स्वास्थ्य केन्द्रों में मरीजों की इलाज की स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारी-कमचारियों को बिना वाजिब कारण के बिल्कुल भी अन्य अस्पतालों में रेफर नही करने के निर्देश दिए। श्रीमती मिश्रा ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को समझाईश देते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कमचारियों का कार्य आम जनता के जीवन से जुड़ा होता है। इसलिए आप सभी का कार्य अत्यंत सम्मानीय एवं आदर्श है। इस कारण से स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही की गुंजाईश बिल्कुल भी नही होती है। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी-कमचारियों को पूरी निष्ठा, ईमानदारी एवं लगन के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने को कहा।

खास खबर

बलौदाबाजार-भाटापारा में नए एसपी राय गौरव रामप्रवेश ने पदभार किया ग्रहण

नई दृष्टिबिंदु / बलौदाबाजार-भाटापारा

भारतीय पुलिस सेवा (भापुसे) 2019 बैच के वरिष्ठ अधिकारी राय गौरव रामप्रवेश ने जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के नए पुलिस अधीक्षक (एसपी) के रूप में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पूर्व राय गौरव रामप्रवेश जिला दंतेवाड़ा में पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे। पुलिस कार्यालय बलौदाबाजार पहुंचने पर निवर्तमान पुलिस अधीक्षक ओपी शर्मा ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने विधिवत रूप से नए पुलिस अधीक्षक को बलौदाबाजार-भाटापारा जिले का चार्ज सौंपा।

इस अवसर पर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक का स्वागत किया। इस दौरान अभिषेक सिंह (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बलौदाबाजार), हेमसागर सिदार (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भाटापारा), तारेश साहू (अनुविभागीय अधिकारी पुलिस SDOP, भाटापारा), कौशल किशोर वासनिक (उप पुलिस अधीक्षक DSP, कैंप कसडोल), संजय साहू (उप पुलिस अधीक्षक DSP, यातायात), उषा सोन्धिया (उप पुलिस अधीक्षक DSP), उषा ठाकुर रक्षित निरीक्षक उपस्थित थे।

सौम्या कामधेनु माता की समाधि स्थल पर बनेगा 'कामधेनु मंदिर धाम', गौसेवा और जीवदया का बनेगा नया केंद्र

खैरागढ़। कामधेनु माता "सौम्या" की समाधि स्थल पर "कामधेनु मंदिर धाम" का निर्माण किया जाएगा। इसकी घोषणा मनोहर गौशाला के संस्थापक एवं मैनेजिंग ट्रस्टी डॉ. अखिल जैन (पदम डाकलिया) ने की। उन्होंने बताया कि यह धाम केवल एक मंदिर नहीं होगा, बल्कि सौम्या माता की करुणा, वात्सल्य, गौभक्ति और जीवदया की प्रेरणा को संजोने वाला आस्था का केंद्र बनेगा।

डॉ. जैन ने कहा कि देशभर से साधु-साध्वी भगवंतों, गौभक्तों, जीवदया प्रेमियों और श्रद्धालुओं ने सौम्या कामधेनु माता के देवलोक गमन पर जो श्रद्धांजलि और संवेदनाएं भेजीं, उनसे यह अनुभव हुआ कि सौम्या केवल मनोहर गौशाला की नहीं, बल्कि पूरे गौभक्त समाज की आस्था का केंद्र थीं। उन्होंने कहा कि इसी भावना को साकार करने के लिए समाधि स्थल को "कामधेनु मंदिर धाम" के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंदिर धाम ऐसा स्थान होगा, जहां श्रद्धालु सौम्या माता को नमन कर सकेंगे, उनकी स्मृतियों से जुड़ सकेंगे और गौसेवा व जीवदया के कार्यों के लिए प्रेरणा प्राप्त करेंगे। उनके अनुसार, श्रद्धालुओं से मिले स्नेह और सहयोग ने गौशाला परिवार को सेवा कार्यों को और अधिक समर्पण के साथ आगे बढ़ाने का संबल दिया है।

राम मंदिर चंदा और चढ़ावा मामले की सुप्रीम कोर्ट निगरानी में जांच हो, जवाबदेही तय करे केंद्र : कांग्रेस नेता रविंद्र चौबे

कांग्रेस ने लगाया आरोप"राम के नाम पर सत्ता भी ली, अब चढ़ावे पर मौन

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता रविंद्र चौबे ने राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे तथा मंदिर में प्राप्त चढ़ावे को लेकर भाजपा, आरएसएस और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम करोड़ों भारतीयों की आस्था, संस्कृति और नैतिक चेतना के प्रतीक हैं, लेकिन भगवान राम के नाम पर जुटाई गई श्रद्धालुओं की आस्था और धन भी कथित रूप से राजनीतिक संरक्षण में लूट का शिकार हो गया। प्रेस वार्ता में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने भी संबोधित किया।

आगे रविंद्र चौबे ने कहा कि देश के गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं और आम श्रद्धालुओं ने अपनी मेहनत की कमाई, गहने और बचत राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पित किए थे। भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार के संगठनों ने करीब तीन दशकों तक भगवान राम के नाम पर आंदोलन चलाया, देशभर से चंदा एकत्र किया और उसी आंदोलन के आधार पर सत्ता तक पहुंचे। आज वही करोड़ों रामभक्त यह पूछने को मजबूर हैं कि भगवान राम के नाम पर जुटाया गया चंदा और मंदिर में प्राप्त चढ़ावा आखिर किसके संरक्षण में कथित रूप से गायब हुआ। उन्होंने कहा कि यह केवल आर्थिक अनियमितता का मामला नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, विश्वास और भावनाओं के साथ किया गया घोर विश्वासघात है। चौबे ने आरोप लगाया कि भाजपा पहले राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे में हेराफेरी के आरोपों से घिरी रही और अब मंदिर के चढ़ावे में भी कथित अनियमितता सामने आ रही है। उन्होंने दावा किया कि रामशिला पूजन अभियान के दौरान 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि एकत्रित की गई थी, लेकिन उस धन का पूरा हिसाब आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया।

उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस के अपने सहयोगी नेताओं ने भी समय-समय पर चंदे को लेकर सवाल उठाए थे। जो लोग मंदिर निर्माण के समय चंदे में कथित हेराफेरी के आरोपों में घिरे थे, वही अब मंदिर बनने के बाद चढ़ावे में भी अनियमितताओं के आरोपों का सामना कर रहे हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की देखरेख में हुआ था, इसलिए यदि ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लग रहे हैं तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की भी बनती है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने भगवान श्रीराम के नाम पर श्रद्धालुओं के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है।

कांग्रेस ने उठाए तीन प्रमुख सवाल : प्रेस वार्ता में रविंद्र चौबे , जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने केंद्र सरकार से तीन प्रमुख सवालों के जवाब मांगे। उन्होंने पूछा कि जब ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री की निगरानी में हुआ तो इस कथित घोटाले की जवाबदेही कौन लेगा? यदि सब कुछ पारदर्शी था तो तत्कालीन महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे क्यों हुए? और यदि कोई अनियमितता नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच से आखिर डर किस बात का है?

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अब तक जो तथ्य सामने आए हैं, वे अत्यंत गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के तत्कालीन महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार किए जा चुके हैं, जो इस बात का संकेत हैं कि मामला केवल प्रशासनिक त्रुटि का नहीं बल्कि गंभीर अनियमितताओं का हो सकता है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि ने भी सार्वजनिक बयान दिए हैं, जबकि वित्तीय निगरानी, पारदर्शिता और संपत्तियों की सुरक्षा की सवीच्च जिम्मेदारी उन्हीं की थी।

उन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ट्रस्ट के विशिष्ट आमंत्रित सदस्य गोपाल राव (गोपाल नगरकोटे) को हटाने तथा उनकी स्थिति को लेकर भी विरोधाभासी जानकारी सामने आई है। वहीं आरएसएस के पूर्व उत्तर प्रदेश प्रभारी कृष्णमोहन को ट्रस्ट का नया महासचिव बनाए जाने पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि उन पर पूरे मामले को दबाने और लीपापोती करने के आरोप लगाए जा चुके हैं।

पीएमओ की भूमिका और बड़े आयोजनों के खर्च पर भी उठाए सवाल : रविंद्र चौबे ने कहा कि यह सार्वजनिक तथ्य है कि ट्रस्ट के प्रशासनिक ढांचे और शीर्ष नियुक्तियों में प्रधानमंत्री कार्यालय की सक्रिय भूमिका रही है। ऐसे में केंद्र सरकार अपनी जवाबदेही से अलग नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि एसआईटी अब राम मंदिर के बड़े आयोजनों के खर्चों की भी जांच कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि 22 जनवरी 2024 को आयोजित प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में लगभग 113 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जिसमें करीब आठ हजार अतिथि शामिल हुए थे। इसके अलावा 25 नवंबर 2025 को आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम पर लगभग 10.12 करोड़ रुपये खर्च होने की बात भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि फर्जी रसीदों, नकद चढ़ावे, लेखा-जोखा में गड़बड़ी तथा कथित हेराफेरी जैसे अनेक आरोप सामने आ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई केवल छोटे कर्मचारियों तक सीमित दिखाई दे रही है, जबकि शीर्ष पदाधिकारियों की जवाबदेही अब तक तय नहीं की गई है।

बद्रीनाथ मंदिर दान मामले का भी किया उल्लेख : कांग्रेस नेता ने कहा कि केवल राम मंदिर ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड के श्री बद्रीनाथ मंदिर से जुड़े हालिया दान घोटाले ने भी गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। उनका कहना था कि इतनी कड़ी सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी और बहुस्तरीय व्यवस्था के बावजूद इतने बड़े स्तर पर कथित अनियमितताएं बिना प्रभावशाली लोगों के संरक्षण के संभव नहीं हो सकतीं। उन्होंने आरोप लगाया कि टुकड़ों-टुकड़ों में इस्तीफे लेना, छोटे कर्मचारियों की गिरफ्तारी करना और सीमित कार्रवाई करना केवल लीपापोती का प्रयास प्रतीत होता है, ताकि बड़े जिम्मेदार लोगों तक जांच की आंच न पहुंचे।

देश के सामने रखे तीन और सवाल : प्रेस वार्ता के अंत में रविंद्र चौबे ने कहा कि देश यह जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले पर मौन क्यों हैं? क्या चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोविंद देव गिरि, गोपाल राव तथा ट्रस्ट के अन्य शीर्ष पदाधिकारी अपनी जवाबदेही से बच सकते हैं? और जब पूरा ट्रस्ट सवालों के घेरे में है तो कार्रवाई केवल छोटे कर्मचारियों तक ही क्यों सीमित है? कांग्रेस मांग करती है कि पूरे प्रकरण की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा दोषी पाए जाने वाले सभी जिम्मेदार लोगों पर समान रूप से कारवाई सुनिश्चित की जाए

भाजपा युवा मोर्चा बिलासपुर ग्रामीण के विभूति कश्यप प्रभारी, सिद्धार्थ शर्मा बने सह प्रभारी

नई दृष्टिबिंदु / बिलासपुर

भारतीय जनता पार्टी के संगठन को ग्रामीण क्षेत्र में और मजबूत करने की दिशा में भाजपा युवा मोर्चा ने बिलासपुर ग्रामीण इकाई के लिए नई नियुक्तियों की घोषणा की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय के मार्गदर्शन में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया ने बिलासपुर ग्रामीण इकाई के लिए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। इसमें विभूति कश्यप को प्रभारी तथा सिद्धार्थ शर्मा को सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

संगठन विस्तार पर फोकस

पार्टी नेतृत्व ने इसे संगठनात्मक मजबूती और ग्रामीण क्षेत्र में युवा मोर्चा की सक्रियता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। नई जिम्मेदारियों के साथ संगठन अब गांव-गांव तक युवाओं तक पहुंच बढ़ाने, पार्टी की नीतियों और जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से पहुंचाने तथा संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने पर काम करेगा।

भाजपा युवा मोर्चा संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान, सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रम, युवा संवाद, सेवा कार्य और जनजागरण अभियानों के माध्यम से लगातार युवाओं को जोड़ने का कार्य करता रहा है। ऐसे में बिलासपुर ग्रामीण इकाई में नई नियुक्तियों को आगामी संगठनात्मक गतिविधियों और कार्यक्रमों की दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है।

नव नियुक्त पदाधिकारियों से अपेक्षाएं

पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने विश्वास जताया है कि प्रभारी विभूति कश्यप और सह प्रभारी सिद्धार्थ शर्मा कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित कर बिलासपुर ग्रामीण क्षेत्र में भाजपा युवा मोर्चा को और अधिक सक्रिय एवं सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

प्रदेश नेतृत्व द्वारा की गई इन नियुक्तियों के बाद स्थानीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने दोनों नव-नियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दीं और संगठन हित में सक्रिय भूमिका निभाने की अपेक्षा व्यक्त की।

नाराजगी और आक्रोश छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी और लंबित मांगें

वादों और हकीकत के बीच फंसे लाखों कर्मचारी, पेंशन और कैशलेस इलाज की फाइलें धूल खा रही

नरेन्द्र डाकलिया / राजनांदगांव

छत्तीसगढ़ के लाखों शासकीय कर्मचारी आज फिर ऊहापोह में हैं। मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी दो बड़ी मांगों पर आज भी धरातल पर अमल नहीं हुआ है। नतीजतन कर्मचारियों में नाराजगी और सोशल मीडिया पर आक्रोश बढ़ता जा रहा है।

दो बड़े मुद्दे लटके

पूर्ण पेंशन के लिए सेवा अवधि 30 वर्ष

6 जुलाई 2023 को तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार ने कैबिनेट में पूर्ण पेंशन के लिए अनिवार्य सेवा अवधि 33 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष करने का निर्णय लिया था। 2019 से चल रही इस मांग पर कर्मचारियों को बड़ी राहत की उम्मीद थी, लेकिन आज तक विधिवत आदेश जारी नहीं हुआ।

कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा

सरकारी अस्पतालों और अनुबंधित निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा को भी कैबिनेट की सहमति

फाइल फोटो

मिल चुकी है। आदेश न आने से कर्मचारी आर्थिक और मानसिक दबाव में हैं।

कैबिनेट निर्णय ही काफी नहीं

नियमों के अनुसार कैबिनेट का फैसला अंतिम नहीं होता। पेंशन जैसी नीतिगत बदलाव के लिए विधि विभाग की समीक्षा, वित्त विभाग की मंजूरी और छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना जरूरी है। बिना गजट नोटिफिकेशन के प्रशासनिक आदेश प्रभावी नहीं माना जाता।

तीन साल में सरकार भी बदली है। प्रशासनिक परंपरा में नई सरकारें पिछली सरकार के अंतिम फैसलों की समीक्षा करती हैं। संभव है फाइलें रिव्यू में हों, लेकिन कर्मचारियों को लग रहा है कि नौकरशाही और कर्मचारी नेताओं के बीच समन्वय नहीं है।

नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल

कर्मचारी संगठनों के फेडरेशन, मंत्रालय कर्मचारी संघ और शिक्षाकर्मी संघ की चुप्पी भी चर्चा में है। कर्मचारी मानते हैं कि इन मुद्दों को प्राथमिकता से मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने नहीं रखा जा रहा। सोशल मीडिया पर बढ़ता आक्रोश इसी का संकेत है।

अब क्या रास्ता?

विशेषज्ञों का मानना है कि शासन को चाहिए कि वह लंबित प्रस्तावों पर स्पष्ट स्टेटस रिपोर्ट सार्वजनिक करे या तत्काल लागू करे। वहीं कर्मचारी संगठनों को भी रणनीति बदलनी होगी। केवल प्रदर्शन तक सीमित न रहकर सरकार से डेटा-ड्रिवन संवाद करना होगा।

अब सवाल यही है कि क्या कर्मचारी संगठन इस मांगों को लेकर फिर से आर-पार की लड़ाई और अनिश्चितकालीन आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे, या बातचीत का दरवाजा खटखटाएंगे।

कलेक्टर मिश्रा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डौण्डीलोहारा का किया निरीक्षण

नई दृष्टिबिंदु / बालोद

कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने आज डौण्डीलोहारा प्रवास के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डौण्डीलोहारा का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में उपस्थित लोगों एवं मरीजों से बातचीत कर अस्पताल के व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधिकारी-कर्मचारियों को अस्पताल में इलाज कराने हेतु आने वाले सभी मरीजों का बेहतर से बेहतर इलाज सुनिश्चित कर उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए। इस मौके पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील चंद्रवंशी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जेएल उइके एवं खण्ड चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारीगण उपस्थित थे।

कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने अस्पताल के पंजीयन कक्ष, ओपीडी कक्ष के अलावा दवा वितरण केन्द्र एवं एनसीडी क्लिनिक आदि का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने पंजीयन कक्ष में पहुँचकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं खण्ड चिकित्सा अधिकारी से पंजीयक कक्ष में किए जा रहे ऑनलाईन एवं ऑफलाईन पंजीयन कार्य के संबंध में जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने दवाई वितरण कक्ष में पहुँचकर अस्पताल के दवाखाने में पर्याप्त मात्रा में दवाइयों के उपलब्धता एवं वितरण आदि की व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने चिकित्सक कक्ष में पहुँचकर मौके पर उपस्थित चिकित्सकों से मरीजों के इलाज के व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली।

मिलाप जावेरी ने अपनी अगली फिल्म में आदित्य रॉय कपूर को क्यों चुना

मिलाप जावेरी अपनी अगली फिल्म को लेकर सुर्खियों में हैं। इसमें वे आदित्य रॉय कपूर के साथ काम कर रहे हैं। यह एक्शन से भरपूर एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म होगी। मिलाप की इस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर लीड रोल निभाने वाले हैं। फिल्म में आदित्य रॉय कपूर की कास्टिंग पर निर्देशक ने हाल ही में बात की।

इन फिल्मों से प्रेरित होगी अगली फिल्म

'सत्यमेव जयते' और 'मरजावां' जैसी एक्शन-एंटरटेनर फिल्में बनाने के लिए मशहूर मिलाप जावेरी ने बताया कि इस फिल्म के लिए आदित्य रॉय कपूर उनकी पहली पसंद थे। निर्देशक ने बॉम्बे टाइम्स से बात करते हुए कहा कि यह फिल्म 'आशिकी 2' और 'एक दीवाने की दीवानियत' जैसी फिल्मों के इमोशनल स्पेस से प्रेरित है, लेकिन साथ ही इसकी अपनी एक अलग पहचान भी होगी। मिलाप जावेरी का कहना है, 'यह फिल्म अपने आप में खास है। यह 'एक दीवाने की दीवानियत' और 'आशिकी 2' जैसी फिल्मों के जेनर की है, लेकिन इसकी अपनी खासियत है। इस बार मैं आम दर्शकों और खास दर्शकों, दोनों तक पहुंचना चाहता हूं यानी सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स, दोनों जगह'। आदित्य फिल्म के लिए पहली पसंद क्यों थे, यह बताते हुए मिलाप ने कहा, 'आदि मेरी पसंद इसलिए थे, क्योंकि 'आशिकी 2' और 'मलंग' से साबित हो चुका है कि आम दर्शकों और महिला दर्शकों के साथ उनका जबर्दस्त जुड़ाव है। वह बेहतरीन एक्टर हैं। हैंडसम हैं। एक्शन के लिए उनकी फिजिक शानदार है। म्यूजिकल फिल्मों में वह बहुत अच्छे लगते हैं'।

क्या हर्षवर्धन राणे के साथ नहीं करेंगे काम?

मिलाप ने हर्षवर्धन राणे की 'एक दीवाने की दीवानियत' का निर्देशन किया है। उन्होंने उन अटकलों को भी खारिज कर दिया कि वे और हर्षवर्धन दोबारा साथ काम नहीं करेंगे। मिलाप ने कहा, 'मैं जल्द ही हर्षवर्धन राणे के साथ फिर से काम करूंगा। मैं उन्हें पसंद करता हूं और वे मेरे दोस्त हैं। अच्छी बात यह है कि हर्ष के पास 'फोर्स 3' और 'सिला' जैसे कई अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं और हम जल्द ही साथ में एक फिल्म जरूर करेंगे'।

क्वीन 2 में नई सोच के साथ लौटेंगी कंगना रनौत

कंगना रनौत की फिल्म 'क्वीन 2' का शूटिंग शेड्यूल पूरा हो चुका है। फिल्म अब पोस्ट-प्रोडक्शन फेज में एंट्री कर चुकी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार यह फिल्म 2014 में आई 'क्वीन' की कहानी को आगे नहीं बढ़ाती, बल्कि उसी विचारधारा को एक नए जीवन परिदृश्य में पेश करती है। इस बार कहानी का केंद्र किसी विदेशी यात्रा या आत्म-खोज की शुरुआत नहीं होगा, बल्कि शादीशुदा जीवन, जिम्मेदारियों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने के संघर्ष पर होगा। फिल्म से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, इस बार कहानी पूरी तरह मुंबई में ही घटित होती है और इसकी लगभग 100 प्रतिशत शूटिंग भी मुंबई के विभिन्न आउटडोर और रियल लोकेशंस पर की गई है।

पहली 'क्वीन' से विचारधारा जुड़ी है, पर कहानी नहीं

सूत्रों का कहना है कि 'क्वीन 2' को सीधे तौर पर पहली फिल्म का सीक्वल नहीं कहा जा सकता। कहानी पहले भाग की घटनाओं को आगे नहीं बढ़ाती और न ही वही किरदार उसी यात्रा पर आगे बढ़ते दिखाई देंगे। हालांकि फिल्म में पहले पार्ट का रेफरेंस या कुछ इमोशनल हिंट देखने को मिल सकते हैं, जिनसे यह समझाया जा सकता है कि एक स्वतंत्र सोच वाली युवती समय के साथ वैवाहिक जीवन में किस तरह प्रवेश करती है और उसके बाद उसके जीवन में क्या बदलाव आते हैं। यानी फिल्म का संबंध कहानी से अधिक उसके मूल विचार व्यक्तिगत आजादी और आत्मसम्मान बताया जा रहा है। पहली फिल्म में यूरोप की यात्रा कहानी का अहम हिस्सा थी। वहीं 'क्वीन 2' में पूरी कहानी मुंबई की पृष्ठभूमि पर आधारित है। सूत्रों ये भी बताते हैं कि फिल्म का हर प्रमुख शेड्यूल मुंबई में ही शूट किया गया है। निर्माताओं ने स्टूडियो सेट की बजाय रियल लोकेशंस का अधिक उपयोग किया ताकि शहर की जीवनशैली और मध्यवर्गीय फैमिली के माहौल को अधिक रियलिस्टिक तरीके से पेश किया जा सके। फिल्म में आउटडोर लोकेशंस की संख्या भी काफी अधिक बताई जा रही है।

'तनु वेड्स...' से अलग कोशिश

वैवाहिक जीवन पर बेस्ड कंगना पहले आर. माधवन के साथ 'तनु वेड्स मनु' भी कर चुकी हैं। सूत्रों का कहना है कि 'क्वीन 2' का दृष्टिकोण उससे अलग है। जहां कई फिल्में पति-पत्नी के रिश्तों में टकराव या रोमांटिक उतार-चढ़ाव पर केंद्रित रहती हैं, वहीं 'क्वीन 2' एक महिला की शादी के बाद के जीवन को नई तरह से पेश करने वाली है। कंगना का अंदाज भी इसमें कुछ अलग होगा।

'क्वीननेस' का एक नया अर्थ भी समझाएगी फिल्म

फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण विचार 'क्वीननेस' है। यहां क्वीन होने का अर्थ किसी शाही जीवन से नहीं, बल्कि व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र पहचान और आत्मविश्वास से जोड़ा गया है। फिल्म यह संदेश देने की कोशिश करती है कि विवाह जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव है लेकिन उसके बाद किसी व्यक्ति की इच्छाएं, करियर, सपने या व्यक्तित्व खत्म नहीं हो जाते। कहानी इस बात पर भी केंद्रित है कि जिम्मेदारियों के बीच भी व्यक्ति अपने भीतर की स्वतंत्र सोच और आत्मसम्मान को कैसे बनाए रख सकता है।

कंगना के अपोजिट दिखेंगे मराठी एक्टर

फिल्म में कंगना के अपोजिट एक मराठी एक्टर को लिया गया है। एक्टर अपेक्षाकृत वरिष्ठ है और कहानी में पति-पत्नी के बीच उम्र का अंतर भी दिखाया गया है। फिल्म पारंपरिक रोमांटिक जोड़ी के बजाय एक अलग तरह के वैवाहिक समीकरण को सामने लाने की कोशिश करती है।

जॉन अब्राहम ने राकेश मारिया के किरदार को निभाना बताया चुनौतीपूर्ण

पिछले काफी वक्त से जॉन अब्राहम रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनने वाली मुंबई के पूर्व कमिश्नर राकेश मारिया की बायोपिक को लेकर चर्चाओं में हैं। हाल ही में जॉन अब्राहम ने राकेश मारिया का किरदार निभाने और असल जिंदगी के लोगों को पर्दे पर उतारने की जिम्मेदारी के बारे में बात की। साथ ही उनका मानना है कि सिनेमा का काम सिर्फ मनोरंजन करना नहीं है। इसे फिल्म खत्म होने के बाद भी दर्शकों के जेहन में बने रहना चाहिए।

फिल्म ऐसी हो जो खत्म होने के बाद भी आपके अंदर रह जाए

टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत के दौरान जॉन ने कहा कि दमदार कहानी कहने का तरीका ऐसा होना चाहिए, जो मनोरंजन करे, सोचने पर मजबूर करे और फिल्म खत्म होने के बाद भी दर्शकों के मन में बसी रहे। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हर कहानी आपको कुछ न कुछ देकर जानी चाहिए। मनोरंजन जरूरी है, सिनेमा को हमेशा आपको जोड़े रखना चाहिए। लेकिन अगर कोई फिल्म थिएटर से निकलने या उसे देखने के बाद भी आपके साथ बनी रहती है, तो यह और भी अच्छी बात है। मैं प्रोजेक्ट्स इसलिए नहीं चुन रहा हूं कि वे कोई खास बात कहना चाहते हैं। मैं उन्हें इसलिए चुनता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि वे ईमानदार हैं, अच्छी तरह से कही गई हैं और भावनात्मक रूप से जोड़ने वाली हैं। अगर उनसे बातचीत शुरू होती है, तो यह एक बोनस है। इतने साल में एक प्रोड्यूसर के तौर पर मुझे एहसास हुआ है कि मैं ऐसी कहानी को सामने लाने में मदद कर सकता हूं जिसे देखा जाना चाहिए। आखिर में, कहानी ही सबसे अहम होती है। अगर वह मुझे प्रभावित करती है, तो मैं उसे सपोर्ट करूंगा।

राकेश मारिया का किरदार निभाने के लिए उत्सुक हूं

मुंबई के पूर्व कमिश्नर राकेश मारिया की बायोपिक को लेकर भी जॉन अब्राहम ने बात की। उन्होंने कहा कि राकेश मारिया का करियर हमारे देश के इतिहास की कुछ अहम घटनाओं से जुड़ा रहा है, इसलिए उन्हें पर्दे पर उतारने में एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास होता है। जब आप किसी असली इंसान का किरदार निभाते हैं, तो मकसद उनकी नकल करना नहीं होता, बल्कि उनकी पब्लिक इमेज के पीछे छिपे असली इंसान को समझना होता है। इसका मतलब है रिसर्च में काफी समय बिताना, उनकी सोच को समझना, उन पर आए दबावों और उनके द्वारा लिए गए फैसलों को जानना। राकेश मारिया का किरदार निभाना एक चुनौती है और मैं इसे पूरी ईमानदारी से निभाने के लिए उत्साहित हूं।

ऋतिक रोशन ने पूरी की 'जेलर 2' में कैमियो की शूटिंग

रजनीकांत इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'जेलर 2' को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म की अभी शूटिंग हो रही है। बताया जाता है कि बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन इस फिल्म में कैमियो करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋतिक रोशन ने फिल्म में अपने कैमियो की शूटिंग पूरी कर ली है। एक्स पर ओम नाम के एक वैरिफाइड यूजर ने एक तस्वीर शेयर की है। इसमें रजनीकांत और ऋतिक रोशन एक साथ नजर आ रहे हैं। नेल्सन दिलीप कुमार ने 'जेलर 2' में ऋतिक रोशन के लिए शानदार किरदार तैयार किया है। उनका एक दमदार सीक्वेंस है। इसके बाद रजनीकांत के साथ एक सीन है। यह एक दमदार कैमियो है, जिसे दर्शकों से तारीफ बटोरने के लिए डिजाइन किया गया है। उनका कैमियो फिल्म के एक अहम मोड़ पर आता है और कहानी को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाता है। 'जेलर 2', रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर एक्शन एंटरटेनर फिल्म 'जेलर' का सीक्वल है।

टॉक्सिक की ट्रोलिंग पर बोलीं हुमा

यश स्टारर फिल्म 'टॉक्सिक' का टीजर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी काफी चर्चा हो रही है। टीजर में दिखाए गए इंटीमेट सीन्स को लेकर कई यूजर्स ने फिल्म की आलोचना की और इसे जरूरत से ज्यादा बोल्ड बताया। कुछ लोगों ने सेंसर बोर्ड को लेकर भी अटकलें लगाईं कि फिल्म के कई सीन काटे जा सकते हैं। इन प्रतिक्रियाओं के बीच फिल्म से जुड़ी एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि दर्शकों ने अभी फिल्म देखी ही नहीं है, इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। हुमा कहती हैं... 'टॉक्सिक में जितनी भी लीड एक्ट्रेसेस हैं, सभी ने शानदार काम किया है। गीतू मोहनदास एक बेहतरीन फिल्ममेकर हैं।

इतनी बड़ी कास्ट बिना मजबूत कहानी के साथ नहीं आती...

उन्होंने नेशनल अवॉर्ड जीता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उनके काम को पहचान मिली है। जब उन्होंने मुझे यह फिल्म ऑफर की, तो मैं इस बात को लेकर उत्साहित थी कि एक महिला निर्देशक इतनी बड़े स्तर की फिल्म कैसे पेश करेंगी। इतनी बड़ी स्टार कास्ट किसी मजबूत कहानी के बिना एक साथ नहीं आती। दर्शकों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए क्योंकि पूरी फिल्म देखने के बाद ही सही तस्वीर सामने आएगी। यह सभी को शॉक्ड कर देगी। यह फिल्म 26 अगस्त को दुनियाभर के थिएटर्स में रिलीज होगी।

जोखिम भरे स्टंट सीन क्यों नहीं करते पृथ्वीराज सुकुमारन? एक्टर ने बताई वजह

पृथ्वीराज सुकुमारन अपने एक्शन सीन खुद करने के लिए मशहूर हैं। मगर, अब वे हैरतअंगेज स्टंट करने के मामले में बेहद सावधानी बरतते हैं और इससे दूरी बनाकर रखते हैं। इसकी वजह साल 2023 का एक हादसा है। एक्टर ने हाल ही में इस बारे में बात की।

अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन इन दिनों फिल्म 'आई, नोबडी' को लेकर सुर्खियों में हैं, जो 09 जुलाई को रिलीज हुई है। पृथ्वीराज ने हाल ही में एक्शन स्टंट को लेकर कहा कि साल 2023 में स्टंट के दौरान लगी चोट ने उन्हें फिल्म 'आई, नोबडी' में एक्शन सीन करने के उनके नजरिए को बदल दिया। उन्होंने बताया कि उस हादसे और सेट पर लगी एक और चोट ने उन्हें इसमें शामिल जोखिमों और जिम्मेदारियों की याद दिलाई।

हादसे ने बदल दिया पूरा तरीका

पृथ्वीराज सुकुमारन ने साल 2023 में हुए उस स्टंट हादसे के बारे में बात की है, जिसने एक्शन सीन करने के उनके तरीके को बदल दिया। एक्टर ने बताया कि उनके बाएं पैर में टाइटेनियम के तीन स्क्रू लगे हैं। एक्टर ने कहा कि इस चोट ने उन्हें एहसास कराया कि पल भर की एक दुर्घटना न सिर्फ उन पर, बल्कि पूरे फिल्म प्रोडक्शन पर असर डाल सकती है।

बाएं घुटने में लगी थी गंभीर चोट

अभिनेता ने अपनी क्राइम थ्रिलर 'आई, नोबडी' के प्रमोशन के दौरान हाल ही में 'द इंडियन एक्सप्रेस' से बात करते हुए कहा कि वे अपने एक्शन सीन खुद करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब वे खतरनाक स्टंट करने को लेकर बहुत ज्यादा सावधान हो गए हैं।

उस हादसे के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, 'मैं साल 2023 में एक और फिल्म की शूटिंग कर रहा था। मेरी पहचान है कि मैं अपने एक्शन सीन खुद करता हूं। एक स्टंट सीन करते समय मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरे बाएं घुटने में काफी गंभीर चोट आई। मुझे तीन सर्जरी करवानी पड़ीं और अब मेरे बाएं पैर में टाइटेनियम के तीन स्क्रू लगे हैं'।

सालभर के लिए रोकनी पड़ी फिल्म की शूटिंग

अभिनेता ने आगे कहा कि हादसे का असर सिर्फ उनकी सेहत पर नहीं पड़ा, बल्कि फिल्म पर भी हुआ। उन्होंने कहा, 'उस फिल्म का काम एक साल के लिए रोकना पड़ा था। बहुत सारा पैसा बर्बाद हुआ और कई लोगों को एक साल तक इंतजार करना पड़ा, इसलिए अब यह जिम्मेदारी मेरे दिमाग में रहती है'। पृथ्वीराज ने 'आई, नोबडी' की शूटिंग के दौरान हुए एक और हादसे को भी याद किया और कहा कि इससे एक्शन फिल्म बनाने में शामिल जोखिमों का पता चलता है। उनके मुताबिक, एक स्टंट करने वाले को गंभीर चोट लगी थी और उसकी गर्दन के पीछे 37 टांके लगाने पड़े थे।

'आई, नोबडी' पर भी हुआ हादसा

एक्टर ने कहा, 'सेट पर हमारे एक फाइटर को चोट लग गई और उनकी गर्दन के पीछे 37 टांके लगाने पड़े। ऐसी चीजें हो जाती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, सोचिए अगर वह शॉट मैं कर रहा होता और मेरे साथ ऐसा होता, तो मुझे छह महीने के लिए घर बैठना पड़ता'। इतनी गंभीर चोट के बावजूद पृथ्वीराज ने कहा कि उन्हें अभी भी एक्शन सीन की शूटिंग करना पसंद है। उन्होंने स्टंट कोऑर्डिनेटर यानिक बेन और उनकी टीम को असल लगने वाले एक्शन सीन डिजाइन करने का श्रेय दिया, जिसमें कलाकारों से काफी मेहनत करवाई गई और हर सीन को असली जैसा दिखाया गया।

उत्कृष्ट प्रदर्शन और त्वरित सेवाओं के लिए सेवा सेतु केन्द्र प्रबंधकों का किया सम्मान

कलेक्टर ने प्रशस्ति पत्र प्रदान कर किया सम्मानित, कहा- सेवा सेतु बना सुशासन और पारदर्शी प्रशासन का प्रभावी माध्यम

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

नागरिकों को शासकीय सेवाएं सरल, सुलभ, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा संचालित "सेवा सेतु परियोजना" जिले में सुशासन का सशक्त माध्यम बनकर उभरी है। लोक सेवा केन्द्रों का उन्नयन कर उन्हें "सेवा सेतु केन्द्र" के रूप में विकसित किए जाने से प्रशासनिक सेवाओं में पारदशिर्ता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ी है। विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को अब आवश्यक प्रमाण-पत्रों एवं अन्य शासकीय सेवाओं के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। इसी उत्कृष्ट कार्य एवं नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने में उल्लेखनीय योगदान के लिए जिला कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में जिले के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सेवा सेतु केन्द्र प्रबंधकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

बेहतर सेवा देने वाले प्रबंधकों को मिला सम्मान : कलेक्टर ने तहसील बेरला की सेवा सेतु केन्द्र प्रबंधक श्रीमती बिंदेश्वरी वर्मा को सेवा सेतु पोर्टल पर प्राप्त कुल आवेदनों में से 99.67 प्रतिशत आवेदनों का सफल अनुमोदन सुनिश्चित कर नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सम्मानित किया। इसी प्रकार तहसील साजा के सेवा सेतु केन्द्र प्रबंधक संदीप देवांगन को 99.65 प्रतिशत आवेदनों के सफल अनुमोदन के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

नागरिकों को समय पर मिल रही महत्वपूर्ण शासकीय सेवाएं : सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, विवाह प्रमाण-पत्र, बी-1, खसरा-नकल, राजस्व प्रकरणों से संबंधित सेवाएं, नाम परिवर्तन हेतु साधारण राजपत्र प्रकाशन, राशन कार्ड, पेंशन सहित अनेक महत्वपूर्ण शासकीय सेवाएं निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे आम नागरिकों का समय और आर्थिक व्यय दोनों की बचत हो रही है तथा सरकारी सेवाओं के प्रति लोगों का विश्वास भी मजबूत हुआ है।

सेवा सेतु बना डिजिटल सुशासन का प्रभावी माध्यम : कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं ने कहा कि सेवा सेतु परियोजना का मूल उद्देश्य आम नागरिकों तक शासकीय सेवाओं को सरल, पारदर्शी, जवाबदेह एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचाना है। अब नागरिक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ही देख सकते हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी है। प्रत्येक सेवा के लिए निर्धारित समय-सीमा होने से आवेदनों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित हो रहा है।

उन्होंने कहा कि सेवा सेतु केन्द्र विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो रहे हैं। अब उन्हें छोटे-छोटे कार्यों या आवश्यक प्रमाण-पत्रों के लिए तहसील अथवा जिला मुख्यालय के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ते, बल्कि उनके नजदीकी सेवा सेतु केन्द्र पर ही अधिकांश शासकीय सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं।

अन्य प्रबंधकों को भी उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किया प्रेरित : कलेक्टर ने सम्मानित सेवा सेतु केन्द्र प्रबंधकों से परियोजना के संचालन एवं कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी ली तथा नागरिक हित में उनके समर्पण, जिम्मेदारी एवं उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की। उन्होंने भविष्य में भी इसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते रहने की शुभकामनाएं देते हुए जिले के सभी सेवा सेतु केन्द्र प्रबंधकों एवं संचालकों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने और जनहित में बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर ई-जिला प्रबंधक महेन्द्र कुमार वर्मा ने भी सम्मानित सेवा सेतु केन्द्र प्रबंधकों को बधाई देते हुए उनके उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की तथा कहा कि सेवा सेतु परियोजना के माध्यम से जिले में नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता एवं पारदशिर्ता लगातार बेहतर हो रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सेवा सेतु केन्द्रों की सक्रिय भूमिका से शासन की डिजिटल सेवाओं का लाभ जिले के प्रत्येक नागरिक तक और अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचेगा तथा सुशासन की अवधारणा को और मजबूती मिलेगी।

खास खबर

गुवारा स्कूल हादसे पर जिला प्रशासन सख्त, मामले में उच्चस्तरीय जांच, जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस, 7 दिन में जांच रिपोर्ट तलब

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

बेमेतरा जिले के विकासखंड साजा अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला गुवारा में कक्षा की छत का प्लास्टर गिरने से दो स्कूली बच्चों के घायल होने की घटना को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं के निर्देश पर मामले की उच्चस्तरीय जांच प्रारंभ कर दी गई है। घटना के संबंध में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जांच एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

घटना में प्रवेश (पिता चन्द्रशेखर) एवं पारस (पिता सुरेश) नामक दो विद्यार्थी घायल हुए हैं। संबंधित विद्यालय भवन का मरम्मत कार्य मुख्यमंत्री जतन योजना के अंतर्गत वर्ष 2023 में स्वीकृत होकर कराया गया था। मरम्मत कार्य की गुणवत्ता एवं निर्माण एजेंसी की भूमिका की जांच के लिए चार सदस्यीय संयुक्त जांच दल का गठन किया गया है। जांच दल में लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता डीके चंदेल, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अनुविभागीय अधिकारी अमर सिंह पैंकरा, सीजीएमएससी के उप अभियंता कमल सिन्हा तथा मंडी बोर्ड के उप अभियंता परवेज बेग को शामिल किया गया है। समिति को सात दिवस के भीतर विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला गुवारा के प्रधान पाठक को कारण बताओ सूचना जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है। नोटिस में उल्लेख किया गया है कि जर्जर भवन में बच्चों को नहीं बैठाने तथा भवन को बंद रखने के पूर्व निर्देशों का पालन नहीं किया गया, जिसके कारण यह घटना हुई। समय-सीमा में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री जतन योजना के अंतर्गत कराए गए मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (आरईएस) के कार्यपालन अभियंता को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में उल्लेख किया गया है कि निर्माण कार्यों में आवश्यक सुधार, निरीक्षण एवं संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध समय पर कार्रवाई नहीं किए जाने से गुणवत्ताहीन कार्य सामने आए। अधिकारी को 24 घंटे के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घटना की निष्पक्ष एवं विस्तृत जांच कर दोषी पाए जाने वाले सभी संबंधित अधिकारियों एवं जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

जीवनदीप समिति के साधारण सभा के लिए सदस्य मनोनीत

राजनांदगांव। स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री गजेन्द्र यादव के अनुमोदन पश्चात जिले में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं में जीवनदीप समिति के साधारण सभा सदस्य के लिए गणमान्यजनों को जीवन दीप समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। जिला चिकित्सालय राजनांदगांव के जीवनदीप समिति की साधारण सभा हेतु गुरूमुख दास वाधवा, राजेश श्यामकर, भागचंद गिडिया, अरविंद सिन्हा, कांती कुमार फुले, आनंद साहू एवं संदीप भट्टाचार्य को सदस्य मनोनीत किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोमनी के जीवनदीप समिति की साधारण सभा हेतु लक्ष्मण यदु, हेमंत साहू, कृष्णा तिवारी, महेश साहू, रामबिलास साहू, जनपद सदस्य डुमेश साहू को सदस्य मनोनीत किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घुमका के जीवनदीप समिति की साधारण सभा हेतु विनोद बारले, नोहेन्द्र सिन्हा, गोविंद सेन, अजय ठाकुर, केदार साहू, जनपद सदस्य श्रीमती अश्वनी मुकेश साहू को सदस्य मनोनीत किया गया है।

इसी तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डोंगरगांव के जीवनदीप समिति की साधारण सभा हेतु प्रफुल्ल जैन, गुलशन पटेल, संदीप जैन, श्रीमती कुन्ती आल्हा, राजेश दवे, हरिशंकर साहू, जनपद सदस्य विवेक मंडावी को सदस्य मनोनीत किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डोंगरगढ़ के जीवनदीप समिति की साधारण सभा हेतु सुरेन्द्र सिंह बन्नोआना, महेन्द्र पटेल, महेन्द्र अग्रवाल, संतोष तिवारी, हरजीत सिंह अरोरा, जनपद सदस्य श्रीमती प्रतिमा खरे, पार्षद हरिश मोडघरे को सदस्य मनोनीत किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छुरिया के जीवनदीप समिति की साधारण सभा हेतु सुरेन्द्र सिंह भाटिया, शिशुपाल साहू, स्वप्निल पटेल, सुरज डडसेना, राधेश्याम शर्मा, जनपद सदस्य उभेराम मंडावी, पार्षद टामेश कुंभकार को सदस्य मनोनीत किया गया है।

सहकारी समितियों में 45144 मीट्रिक टन व निजी क्षेत्र में 18589 मीट्रिक टन उर्वरकों का भंडारण

जिले में 14686 क्विंटल बीज का भंडारण, किसानों को 13700 .82 क्विंटल बीज का किया गया वितरण

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

राजनांदगांव जिले में खरीफ 2026 अंतर्गत धान, मक्का, सोयाबीन, अरहर, उड़द, मूंग सहित अन्य फसलों की बुवाई का कार्य प्रगतिरत है। किसानों के लिए खाद-बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने कहा कि किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को किसानों को खाद-बीज उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। जिले में खरीफ 2026 हेतु 14331 क्विंटल बीज की मांग के विरूद्ध 14686 क्विंटल बीज भंडारण कराकर 13700.82 क्विंटल बीज किसानों को समिति एवं कृषि विभाग के माध्यम से वितरण कराया गया है। बीजों का भंडारण वर्तमान लक्ष्य के विरूद्ध 102 प्रतिशत हैं एवं भंडारण के विरूद्ध वितरण 93 प्रतिशत है। अद्यतन 112884.92 हेक्टेयर रकबा में खरीफ फसलों की बुवाई का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिसमें धान फसल की 111339 हेक्टेयर रकबा में की बुवाई व रोपाई का कार्य पूर्ण हो चुका है।

खरीफ फसलों के लिए रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु इस वर्ष सहकारी क्षेत्र में 45650 मीट्रिक टन एवं निजी क्षेत्र में 23310 मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य के विरूद्ध 45144 मीट्रिक टन उर्वरक सहकारी समितियों में एवं निजी क्षेत्र में लक्ष्य के विरूद्ध 18589 मीट्रिक टन उर्वरकों का भंडारण किया जा चुका है, जो निर्धारित लक्ष्य का 92 प्रतिशत है। जिले में लक्ष्य की तुलना में सहकारी एवं निजी क्षेत्रों से यूरिया 23561 मीट्रिक टन, एसएसपी 8570 मीट्रिक टन, एमओपी 3259 मीट्रिक टन, डीएपी 4704 मीट्रिक टन एवं एनपीके 11443 मीट्रिक टन किसानों को वितरण किया जा चुका है, जो कि भंडारण की तुलना में 80 प्रतिशत हैं। उप संचालक कृषि श्री टीकम सिंह ठाकुर ने सभी समितियों एवं निजी उर्वरक विक्रेताओं से अपील की है कि किसानों को उर्वरकों के उठाव में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो तथा किसानों को खाद एवं बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

24 उर्वरक विक्रय केंद्रों में अनियमितता पर कारण बताओ नोटिस, दो केंद्रों पर बिक्री प्रतिबंध की कार्रवाई

मोहला। खरीफ वर्ष 2026 के दौरान किसानों को समय पर गुणवत्तायुक्त बीज एवं उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन और कृषि विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर वितरण एवं गुणवत्ता नियंत्रण की कार्रवाई की जा रही है। जिले में अब तक उपलब्ध बीजों का 93 प्रतिशत तथा उर्वरकों का 82 प्रतिशत किसानों को वितरित किया जा चुका है। कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार शासन के नवीन निर्देशों के तहत अब किसानों को यूरिया एवं डीएपी की आवश्यक मात्रा एक ही बार में उपलब्ध कराई जा रही है। जिले की सभी सहकारी समितियों और निजी उर्वरक विक्रय केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में खाद एवं उर्वरक उपलब्ध हैं, जिससे किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। गुणवत्ता बनाए रखने तथा कालाबाजारी, अवैध भंडारण और अन्य अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए जिलेभर में सघन निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान 10 बीज विक्रय केंद्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, जबकि खेती मित्र कृषि केंद्र, मोहला की बीज अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी गई। गुणवत्ता परीक्षण के लिए 61 बीज नमूने प्रयोगशाला भेजे गए हैं। इसके साथ ही 72 उर्वरक विक्रय केंद्रों के निरीक्षण में 24 केंद्रों में अनियमितताएं पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए तथा दो केंद्रों पर बिक्री प्रतिबंध की कार्रवाई की गई। उर्वरकों के 22 नमूने भी गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। इसके अतिरिक्त, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में चन्द्रा कृषि केंद्र, अंबागढ़ चौकी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कलेक्टर न्यायालय ने शासन के पक्ष में 31 हजार 740 रुपए राजसात करने के आदेश दिए। जब्त जैव उत्प्रेरक नियमानुसार संबंधित प्रतिष्ठान के सुपुर्द किया गया। जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत विक्रय केंद्रों से ही बीज एवं उर्वरक खरीदें तथा अधिक मूल्य वसूली, कालाबाजारी या किसी भी प्रकार की अनियमितता की जानकारी तत्काल कृषि विभाग को दें।

खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत वर्ष 2026 में खरीफ फसलों के फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष अलनीनो के प्रभाव के कारण जिले में कम बारिश की संभावना बनी हुई है। ऐसी स्थिति में फसलों को प्रतिकूल मौसम एवं स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए ऋणी एवं अऋणी कृषकों का भू-धारक अथवा बटाईदार के रूप में पंजीयन किया जाना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के किसान मुख्य फसल धान सिंचित, धान असिंचित एवं अन्य फसल मक्का, सोयाबीन, मूंगफल्ली, अरहर, उड़द, मूंग, कोदो, कुटकी, रागी का बीमा करा सकते है।

खरीफ 2026 के लिए जिले में फसलवार बीमांकित व ऋणमान राशि एवं किसान की देय प्रीमियम राशि जारी की गई है। कृषक द्वारा देय प्रीमियम दर 2 प्रतिशत है। धान सिंचित के लिए बीमांकित राशि 66000 रूपए प्रतिहेक्टेयर एवं किसान की देय प्रीमियम राशि 1320 रूपए प्रति हेक्टेयर, धान असिंचित के लिए बीमांकित राशि 49500 रूपए प्रतिहेक्टेयर एवं किसान की देय प्रीमियम राशि 990 रूपए प्रति हेक्टेयर, मक्का के लिए बीमांकित राशि 52800 रूपए प्रतिहेक्टेयर एवं किसान की देय प्रीमियम राशि 1956 रूपए प्रति हेक्टेयर, सोयाबीन के लिए बीमांकित राशि 55000 रूपए प्रति हेक्टेयर एवं किसान की देय प्रीमियम राशि 1100 रूपए प्रति हेक्टेयर, मूंगफल्ली के लिए बीमांकित राशि 46200 रूपए प्रति हेक्टेयर एवं किसान की देय प्रीमियम राशि 924 रूपए प्रति हेक्टेयर, अरहर के लिए बीमांकित राशि 44000 रूपए प्रति हेक्टेयर एवं किसान की देय प्रीमियम राशि 880 रूपए प्रति हेक्टेयर, उड़द के लिए बीमांकित राशि 33000 रूपए प्रति हेक्टेयर एवं किसान की देय प्रीमियम राशि 660 रूपए प्रति हेक्टेयर, मूंग के लिए बीमांकित राशि 31900 रूपए प्रति हेक्टेयर एवं किसान की देय प्रीमियम राशि 638 रूपए प्रति हेक्टेयर, कोदो के लिए बीमांकित राशि 24200 रूपए प्रति हेक्टेयर एवं किसान की देय प्रीमियम राशि 484 रूपए प्रति हेक्टेयर, कुटकी के लिए बीमांकित राशि 24200 रूपए प्रति हेक्टेयर एवं किसान की देय प्रीमियम राशि 484 रूपए प्रति हेक्टेयर, रागी के लिए बीमांकित राशि 27500 रूपए प्रति हेक्टेयर एवं किसान की देय प्रीमियम राशि 550 रूपए प्रति हेक्टेयर निर्धारित है।

अधिसूचित ग्राम व राजस्व निरीक्षक मंडल में अधिसूचित फसल के लिए ऋणी कृषक स्वीकृत व नवीनीकृत मौसमी कृषि ऋण के आधार पर वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से एवं अऋणी कृषक बोवाई प्रमाण पत्र, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित कराकर अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर लोक सेवा केन्द्रों व बैंक के माध्यम से अथवा स्वयं फार्मर एप से पंजीयन कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते है। आवेदन के साथ नवीनतम आधार कार्ड की कॉपी, नवीनतम भूमि प्रमाण पत्र (बी-1, पी-2 की कॉपी), बैंक पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी जिस पर खाता नबंर, आईएफसी कोड, बैंक का पता साफ दिख रहा हो, फसल बोवाई प्रमाण-पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्वघोषणा पत्र, किसान का वैध मोबाईल नंबर, बटाईदार, कास्तकार का घोषणा पत्र दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बालिकाओं को दिए जा रहे आत्मरक्षा के गुर

शहीद पंकज विक्रम सम्मान से सम्मानित मार्शल आर्ट प्रशिक्षक भानु प्रताप साहू सिखा रहे सेल्फ डिफेंस, आत्मविश्वास और अनुशासन के पाठ

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बेमेतरा द्वारा भारत सरकार की "बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ" योजना के अंतर्गत जिले की किशोरी बालिकाओं को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी एवं सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से 20 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण जिला कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं के निर्देशानुसार तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी चन्द्रबेश सिंह सिसोदिया के मार्गदर्शन में महिला सशक्तिकरण केन्द्र (हब) के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।

प्रशिक्षण का आयोजन परियोजना बेमेतरा एवं नवागढ़ के अंतर्गत पी.एम. स्वामी आत्मानंद शासकीय कन्या विद्यालय, नवागढ़ तथा शासकीय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय, बेमेतरा में किया जा रहा है। प्रशिक्षण में बड़ी संख्या में किशोरी बालिकाएं उत्साहपूर्वक भाग लेकर आत्मरक्षा के आधुनिक एवं प्रभावी गुर सीख रही हैं।

शहीद पंकज विक्रम सम्मान से सम्मानित प्रशिक्षक दे रहे प्रशिक्षण : प्रशिक्षण का संचालन शहीद पंकज विक्रम सम्मान से सम्मानित एवं द वॉर क्राई मार्शल आर्ट्स एंड सेल्फ डिफेंस एकेडमी, बेमेतरा के प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर भानु प्रताप साहू द्वारा किया जा रहा है। उनके मार्गदर्शन में बालिकाओं को व्यावहारिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिससे वे किसी भी आपात अथवा विषम परिस्थिति में अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें।

कराटे, किक बॉक्सिंग, वुशू सहित कई तकनीकों का दिया जा रहा प्रशिक्षण : प्रशिक्षण के दौरान बालिकाओं को किक बॉक्सिंग, कराटे, वुशू, सेल्फ डिफेंस तकनीक, पंच, किक, ब्लॉक, काता, शारीरिक व्यायाम एवं फिटनेस का अभ्यास कराया जा रहा है। साथ ही उन्हें यह भी सिखाया जा रहा है कि किसी भी अनहोनी या संकट की स्थिति में बिना किसी हथियार के किस प्रकार सूझबूझ एवं आत्मविश्वास के साथ स्वयं की सुरक्षा की जा सकती है।

आत्मरक्षा के साथ आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विकास पर भी जोर : इस प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल आत्मरक्षा की तकनीक सिखाना ही नहीं, बल्कि बालिकाओं में आत्मविश्वास, आत्मअनुशासन, सकारात्मक सोच, सामाजिक व्यवहार, मानसिक दृढ़ता एवं शारीरिक फिटनेस का विकास करना भी है। प्रशिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को मोबाइल की बढ़ती लत से दूर रहकर स्वस्थ एवं अनुशासित जीवनशैली अपनाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है।

महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल : महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बालिकाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे बालिकाएं न केवल स्वयं की सुरक्षा करने में सक्षम बन रही हैं, बल्कि उनमें आत्मसम्मान, साहस और नेतृत्व क्षमता का भी विकास हो रहा है। विभाग का उद्देश्य है कि प्रत्येक बालिका आत्मविश्वास के साथ शिक्षा ग्रहण करे और जीवन की हर चुनौती का दृढ़ता से सामना कर सके।

आर्थिक सब्बल जिले के 37 हजार 131 संग्राहक परिवारों को 30 करोड़ 65 लाख 79 हजार रुपए से अधिक का हुआ भुगतान

हरा सोना ने बदली जिंदगी, ग्रामीणों के लिए बना आर्थिक संबल

नई दृष्टिबिंदु / मोहला

जिले के घने वन क्षेत्रों में तेंदूपत्ता हरा सोना केवल एक वनोपज नहीं बल्कि हजारों आदिवासी और ग्रामीण परिवारों की आजीविका का आधार भी है। हर वर्ष गर्मी के मौसम में ग्रामीण परिवार विशेषकर महिलाएं, तेंदूपत्ता संग्रहण के कार्य में जुट जाते हैं। यह कार्य उनके लिए अतिरिक्त आय का प्रमुख स्रोत बनकर परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। जिले के ग्रामों में रहने वाली बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण तेंदूपत्ता संग्रहण से प्राप्त आय का उपयोग बच्चों की शिक्षा, घरेलू आवश्यकताओं और खेती-किसानी के कार्यों में करते हैं। यही कारण है कि तेंदूपत्ता संग्रहण को ग्रामीण रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण का मजबूत माध्यम माना जाता है।

वर्ष 2026 में जिले की 39 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के अंतर्गत 40 लॉट में 502 फड़ों के माध्यम से तेंदूपत्ता संग्रहण किया गया। मई माह में कुल 55 हजार 741.7 मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण 37 हजार 131 संग्राहक परिवारों द्वारा किया गया। इस संग्रहण के एवज में संग्राहक परिवारों को 30 करोड़ 65 लाख 79 हजार 350 रुपए का भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त फरवरी-मार्च 2026 में तेंदूपत्ता बूटा कटाई के लिए 40 लाख 51 हजार 154 रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है।

गुणवत्ता के कारण जिले के तेंदूपत्ते की बढ़ी पहचान : जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी का तेंदूपत्ता अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि जिले के तेंदूपत्ता लॉट प्रतिवर्ष ठेकेदारों द्वारा उच्च दर पर खरीदे जाते हैं। वर्ष 2023 के तेंदूपत्ता संग्रहण के लिए जिले की 36 समितियों के 33 हजार 363 संग्राहक परिवारों को 11 करोड़ 97 लाख 98 हजार 934 रुपए बोनस राशि के रूप में प्रदान किए जाने की कार्रवाई की जा रही है।

पारदर्शी व्यवस्था से समय पर भुगतान : तेंदूपत्ता बूटा कटाई और संग्रहण के भुगतान के लिए ऑनलाइन व्यवस्था लागू की गई है। डीबीटी प्रणाली के माध्यम से राशि सीधे संग्राहकों के बैंक खातों में भेजी जा रही है, जिससे भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदूपत्ता संग्रहण से मिलने वाली आय उनके लिए आर्थिक संबल बन गई है। इससे न केवल परिवार की जरूरतें पूरी हो रही हैं, बल्कि महिलाएं भी आर्थिक रूप से सशक्त होकर आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रही हैं।

नवीन नवोदय विद्यालय के संचालन के लिए आईटीआई भवन का कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने किया निरीक्षण

नई दृष्टिबिंदु / मोहला

कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने अंबागढ़ चौकी विकासखंड का दौरा कर नवीन जवाहर नवोदय विद्यालय के संचालन के लिए प्रस्तावित शासकीय आईटीआई भवन एवं छात्रावास का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय के सफल संचालन के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्रीमती प्रजापति शासकीय आईटीआई कॉलेज परिसर पहुंचींए जहां उन्होंने 40 सीटर नवोदय आवासीय विद्यालय के संचालन के लिए प्रस्तावित कक्षाओं एवं छात्रावास भवन का अवलोकन किया। उन्होंने विद्यालय के सुचारु एवं गुणवत्तापूर्ण संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाओंए कक्षाओं की उपलब्धता तथा छात्रावास की सुविधाओं के संबंध में अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की।

कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को आईटीआई हॉस्टल भवन का लेआउट तैयार कर नवोदय विद्यालय के संचालन के अनुरूप आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा सभी आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के लिए सुरक्षितए सुव्यवस्थित एवं अध्ययन के अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता हैए ताकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं बेहतर आवासीय सुविधाएं मिल सकें।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने अंबागढ़ चौकी स्थित विकासखंड स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र भवन के निर्माण कार्यों का भी अवलोकन किया। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित एजेंसी एवं अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि भवन का उपयोग निर्धारित समय पर प्रारंभ किया जा सके। इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

निगम आयुक्त सुरूचि सिंह का 3 जोनों का निरीक्षण, सफाई, उद्यान व पेयजल गुणवत्ता पर किया फोकस

समय-सीमा में काम पूरा करने के निर्देश

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

"स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई" अभियान के तहत नगर पालिक निगम भिलाई की आयुक्त सुश्री सुरूचि सिंह ने गुरुवार को शहर के विभिन्न जोनों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं गुणवत्ता के साथ उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।

जोन-5, 3 और 2 का किया दौरा : आयुक्त ने सबसे पहले जोन-05 के सेक्टर-06 स्थित श्रीराम चौक की सफाई व्यवस्था देखी और नियमित व प्रभावी सफाई सुनिश्चित करने को कहा। इसके बाद वार्ड-69 हुडको स्थित शहीद स्मारक गार्डन का निरीक्षण कर उद्यान की साफ-सफाई, हरियाली और आवश्यक सुधार कार्य शीघ्र कराने के निर्देश दिए।

वार्ड-67 में उन्होंने नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पानी की गुणवत्ता जांची। अधिकारियों को समय-समय पर जल गुणवत्ता परीक्षण कराने और व्यवस्था सुचारू रखने को कहा।

उद्यान और बायोरेमेडिएशन का लिया जायजा : इसके बाद आयुक्त जोन-03 के वार्ड-36 टाटा लाइन गार्डन पहुंचीं। यहां उद्यान की साफ-सफाई और रखरखाव की समीक्षा की। वार्ड-28 में भी पेयजल की शुद्धता जांची गई। निरीक्षण के अंतिम चरण में आयुक्त जामुल स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचीं। यहां चल रहे बायोरेमेडिएशन कार्यों की प्रगति और अपनाई जा रही तकनीकी प्रक्रिया का अवलोकन किया। उन्होंने पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान जोन आयुक्त अजय गौर, कुलदीप गुप्ता, अमरनाथ दुबे, कार्यपालन अभियंता अनिल सिंह, अरविंद शर्मा, स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे। आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि शहर में नागरिक सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

शिकायतों के त्वरित निराकरण और ई-ऑफिस लागू करने के दिए निर्देश

नगर पालिक निगम भिलाई की आयुक्त सुश्री सुरूचि सिंह ने गुरुवार को निगम सभागार में अधिकारियों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। बैठक में शहर की मूलभूत सुविधाओं, पर्यावरण संरक्षण और जनशिकायतों के त्वरित निराकरण पर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक के प्रमुख निर्देश

स्ट्रीट लाइट व्यवस्था दुरुस्त होगी: आयुक्त ने शहर की प्रकाश व्यवस्था बेहतर करने के लिए स्ट्रीट लाइट मरम्मत के आगामी टेंडर सीधे जोन स्तर से करने के निर्देश दिए। इससे शिकायतों का स्थानीय स्तर पर त्वरित समाधान हो सकेगा।

रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्राथमिकता: गिरते भूजल स्तर को देखते हुए शहर में वर्षा जल संचयन के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने को कहा गया। आयुक्त ने शहरवासियों से भी अपने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की अपील की।

बड़े स्तर पर पौधारोपण: भिलाई को हरा-भरा बनाने के लिए बड़े पैमाने पर पौधारोपण और ट्री-गार्ड जैसे सुरक्षा उपायों पर विशेष जोर दिया गया।

शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण: मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण और समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

विकास कार्य और पारदर्शिता: 15वें वित्त आयोग के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति समीक्षा की गई। निगम के बकाया बिजली बिलों के भुगतान और खपत नियंत्रण पर भी चर्चा हुई। सभी विभागों को शत-प्रतिशत ई-ऑफिस प्रणाली से कार्य करने को कहा गया।

आयुक्त ने कहा "नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना और पर्यावरण का संरक्षण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

19 जुलाई को राष्ट्र संत मणिभद्र मुनि का दुर्ग में भव्य नगर प्रवेश

7 दिन तक विभिन्न क्षेत्रों में विचरण, 26 जुलाई को होगा चातुर्मास प्रवेश

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक श्रमण संघ के तत्वावधान में राष्ट्र संत, मानव मिलन के संस्थापक परम पूज्य गुरुदेव श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज का भव्य नगर प्रवेश रविवार 19 जुलाई को श्रद्धा एवं भक्ति भाव के साथ किया जाएगा।

सुबह 7:40 बजे होगी आगवानी : आयोजकों के अनुसार नगर प्रवेश यात्रा प्रातः 7:40 बजे पूज्य म.सा. सुरेश जी जैन के नेहरू नगर स्थित स्थान से विहार कर प्रारंभ होगी। इस पावन अवसर पर चतुर्विध संघ की विशेष उपस्थिति रहेगी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुरु दर्शन एवं मंगल विहार का लाभ लेंगे। साइंस कॉलेज ओवर ब्रिज के पास गुरुदेव की आगवानी की जाएगी। आगवानी में श्रमण संघ परिवार के वरिष्ठ श्रावक-श्राविकाओं के साथ श्रमण संघ वर्धमान सेवा मंच, स्वाध्याय मंडल, महिला मंडल, बालिका मंडल एवं आनंद मधुकर रतन पाठशाला के बच्चे विशेष रूप से शामिल होंगे।

आध्यात्मिक जागृति का संदेश : आयोजकों ने बताया कि गुरुदेव श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज राष्ट्र संत एवं मानव मिलन के प्रणेता के रूप में समाज में आध्यात्मिक जागृति, नैतिक मूल्यों तथा मानवीय एकता का संदेश दे रहे हैं। उनके दुर्ग आगमन को लेकर समाज में विशेष उत्साह का माहौल है। संघ ने नगर प्रवेश में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं से मुंहपत्ती लगाकर पधारने और धर्मलाभ प्राप्त करने का अनुरोध किया है।

19 से 25 जुलाई तक होगा क्षेत्रीय विचरण : नगर प्रवेश के बाद 19 जुलाई से 25 जुलाई तक संत समुदाय शहर के विभिन्न क्षेत्रों मालवीय नगर, पदमनाभपुर, आदर्श नगर, महावीर कॉलोनी, खंडेलवाल कॉलोनी एवं ऋषभ नगर का विचरण करते हुए वर्धमान हाइट्स पहुंचेंगे।

26 जुलाई को चातुर्मास प्रवेश : आगामी 26 जुलाई को राष्ट्र संत श्री मणिभद्र मुनि जी एवं साध्वी लक्ष्मी जी म.सा. अपने साध्वी समुदाय के साथ वर्धमान हाइट्स से जय आनंद मधुकर रतन भवन, बांधा तालाब दुर्ग में चातुर्मास हेतु भव्य प्रवेश करेंगे। इसमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से श्रमण संघ परिवार के सदस्य एवं गुरु भक्त परिवार शामिल होंगे। वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक श्रमण संघ, दुर्ग ने समस्त जैन समाज एवं धर्मप्रेमी नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर नगर प्रवेश को सफल बनाने का आह्वान किया है।

बेमेतरा में श्री जगन्नाथ की निकली रथयात्रा

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

बेमेतरा जिला मुख्यालय में भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथयात्रा श्रद्धा, आस्था और उत्साह के साथ निकाली गई। हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस धार्मिक आयोजन में शामिल हुए और पूरे शहर में भक्तिमय माहौल देखने को मिला। भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की भव्य शोभायात्रा बड़े ही धूमधाम और धार्मिक उल्लास के साथ निकाली गई।

शोभायात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए नगर भ्रमण पर निकली, जहां जगह-जगह श्रद्धालुओं ने भगवान की आरती उतारकर पुष्पवर्षा करते हुए स्वागत किया। यात्रा में महिला, पुरुष, युवा और बच्चों सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पूरे मार्ग में जय जगन्नाथ के जयकारों, भजन-कीर्तन और ढोल-नगाड़ों की गूंज से वातावरण भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालु भगवान के रथ को खींचने के लिए उत्साहित नजर आए और पूरे आयोजन में धार्मिक आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिला।

आयोजन समिति द्वारा यात्रा की समुचित व्यवस्था की गई थी, वहीं सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। बेमेतरा में निकली भगवान श्री जगन्नाथ की यह भव्य रथयात्रा श्रद्धा, भक्ति और सामाजिक एकता का संदेश देती नजर आई। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी ने आयोजन को और भी भव्य बना दिया।

GOSWWAMI
FLEX PRINTING
ADVERTIZER
भिलाई में सबसे सस्ता, सबसे अच्छा
Hoardings • Flex Banner • Vinyl Printing
One Way Vision • Glow Sign Board
93290-13334, 74711-15735
goswamiflex@gmail.com
Address - 3rd Floor Shop No-1, Arora Tower, M.C. Market

अर्चना
फ्लाई ऐश ब्रिक्स
निर्माता एवं विक्रेता
हैवी इंडस्ट्रीयल एरिया, भिलाई
8 इंच एवं 9 इंच में उपलब्ध है।
संपर्क करें
9329960605, 9827160605, 9098639991

Baked by Suhani
Premium Homemade Cakes & Desserts
Birthday Cakes
Anniversary Cakes
Custom Theme Cakes
Serving Bhilai & Durg
baked.by.suhani
Suhani Singh
Premium Homemade Cakes & Desserts
Serving Bhilai & Durg
DM for Order
Followed by _s_andeep
Follow
Message
Order Now:
@baked.by.suhani
M0.6263734520

10वीं, 12वीं, स्नातक एवं स्नातकोत्तर पास छात्र-छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए
फायर एवं सेफ्टी प्रशिक्षण
नौकरी में सहायक
सत्र 2026-2027 प्रवेश प्रारंभ
निजी कंपनियां जैसे पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट, स्टील प्लांट, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत नौकरियाँ मिलती है।
प्रशिक्षण शुल्क में विशेष छूट
सरकारी मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र दिया जाएगा
फायर एवं सेफ्टी प्रशिक्षण में प्रवेश प्रारंभ

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	क्र.	पाठ्यक्रम का नाम
1.	फायर टेक्नोलॉजी एण्ड इंडस्ट्रियल सेफ्टी	5.	पी. जी. कोर्स व्यावसायिक सेफ्टी, स्वास्थ्य व पर्यावरण मैनेजमेंट सिस्टम
2.	इंडस्ट्रियल सेफ्टी / पी. जी. इंडस्ट्रियल सेफ्टी	6.	हैल्थ सेनेटरी इंस्पेक्टर
3.	बी.एस.सी. इन फायर सेफ्टी	7.	सब- फायर ऑफिसर
4.	पी. जी. कोर्स फायर एवं इंडस्ट्रियल सेफ्टी	8.	सर्टिफिकेट इन फायरमैन-इंडस्ट्रियल सेफ्टी

(An Authorized Training Centre of AEERO)
फायर सेफ्टी एवं डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट
(मान्यता प्राप्त निजी प्रशिक्षण संस्थान)
कैंपस :- इंदिरा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, सुपेला, भिलाई, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़
ADMISSION HELPLINE: 7697212782

BA
BCA
BCom
BBA
BSc
PGDCA
MSc CHEMISTRY
MSc BIOTECHNOLOGY
MSc BOTANY
MSc ZOOLOGY
MSc COMPUTER Sc
MSc MATHS
MA ENGLISH
MCom
BLib
MLib
DCA
MA CHHATTISGARHI
Affiliated to Hemchand Yadav University, Durg
SAI COLLEGE
Street-69, Sector-6, Bhilai
70248 86996
99770 01027
Deepak Advertisers

"यह समाचार पत्र आलोक तिवारी द्वारा 80/बी, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग, (छत्तीसगढ़)-490023 से आलोक तिवारी की ओर से प्रकाशित की जाती है, जिसका संपादन आलोक तिवारी द्वारा किया जाता है तथा इसका मुद्रण समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स द्वारा प्लॉट नं. 339/6, गली नं. 02, पाटन, थाना उतई, दुर्ग, (छ.ग.)-491111 पर किया जाता है। (समाचार चयन के लिए PRP Act, 2023 के तहत संपादक जिम्मेदार है)। समस्त विवादों का निपटारा न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।" संपादक आलोक तिवारी, मो. 74154-69100